वर्ष 12 • अंक 304 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 8 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

इस्पात के दाम बढ़ते रहने पर संशय

मोहन गोयनका ▶▶ पृष्ठ 3

मार्च 2021 तक प्रवर्तकों के गिरवी शेयर छुड़ा लेंगे

डॉलर रु. 71.40 ▲ 20 पैसे | यूरो रु. 78.20 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40503 ▲ 167 रुपये | सेंसेक्स 41141.90 ▼ 164.20 | निफ्टी 12098.30 ▼ 39.60 | निफ्टी फ्यूचर्स 12095.90 ▼ 02.40 | ब्रेंट क्रूड 53.90 डॉलर ▼ 0.60 डॉलर

एक नज़र

एसबीआई ने घटाई जमा और उधारी दरें

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने खुदरा और थोक जमा पर ब्याज दरों में 10 से 50 आधार अंक की कटौती की है। ये दरें 10 फरवरी से लागू होंगी। बैंक ने साथ ही सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर सीमांत कोष की लागत पर आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 5 आधार अंक की कटौती की है। इस कटौती के बाद एक साल वाले परिपक्वता अवधि वाले ऋण का एमसीएलआर 7.85 फीसदी रह गया है। पृष्ठ 4

टाटा स्टील को 236 करोड़ रुपये का घाटा

देश की सबसे पुरानी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील को दिसंबर तिमाही में 236 करोड़ रुपये का एकीकृत कर पूर्व घाटा हुआ है। बिक्री में कमी और यूरोपीय परिचालन में संपत्ति के निर्धारित मूल्य में कमी के एवज में किए गए प्रावधान से कंपनी को घाटा हुआ है। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी ने 3,140 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी की शुद्ध बिक्री दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में घटकर 34,774 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इस तिमाही में 38,086 करोड़ रुपये थी।

12 प्रमुख बंदरगाहों पर जांच के निर्देश

कोरोनावायरस से बचाव के उपायों के तहत सरकार ने देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को तत्काल जांच, पहचान और पृथक करने की प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। ऐहतियाती उपायों के तहत समुद्री नाविकों और क्रूज यात्रियों को निकालने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने यह प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने राज्यसभा में बताया कि अभी तक कुल 1,275 उड़ानों में 1,39,539 यात्रियों की जांच की गई है। इन यात्रियों में से 150 में लक्षण मिलने पर उन्हें पृथक सुविधाओं में रखा गया है। पृष्ठ 14

क्रेडिट सुइस के सीईओ ने दिया इस्तीफा

स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट सुइस के मुख्य कार्याधिकारी टी. थियाम ने इस्तीफा दे दिया है और वह अगले सप्ताह अपना पद छोड़ देंगे। बैंक के स्विस परिचालन के मौजूदा प्रमुख थॉमस गॉट्सटीन उनका स्थान लेंगे। बैंक पर अपने कर्मचारियों और पूर्व शीर्ष कार्यकारी की जासूसी करने का आरोप लगा था। साथ ही वह ग्रीनपीस पर भी नजर रख रहा था। इन आरोपों के कारण थियाम की मुश्किलें बढ़ गई थी। थियाम ने एक बयान में कहा कि उन्होंने बोर्ड की राय पर सहमति जताते हुए सीईओ पद छोड़ने का फैसला किया है।

आज का सवाल

क्या व्हाट्सऐप पे के आने के बाद भुगतान खंड में बढ़ेगी प्रतिस्पर्द्धा

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या आरबीआई के कदम से बैंकिंग तंत्र में बढ़ेगी नकदी
हां **55.56%**
नहीं **44.44%**

व्हाट्सऐप से भी होगा भुगतान

फेसबुक नियंत्रित व्हाट्सऐप चरणबद्ध रूप में करेगी अपनी भुगतान सेवा की शुरुआत

सोमेश झा और नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 7 फरवरी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने फेसबुक नियंत्रित व्हाट्सऐप को डिजिटल भुगतान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। कंपनी अपनी भुगतान सेवा 'व्हाट्सऐप पे' की शुरुआत चरणबद्ध रूप में करेगी। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि पहले चरण में व्हाट्सऐप भारत में 1 करोड़ उपभोक्ताओं को अपनी भुगतान सेवा की सुविधा देगी।

कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी इसके लिए व्हाट्सऐप को हरी झंडी दे दी थी। सूत्र के अनुसार व्हाट्सऐप ने आरबीआई और एनपीसीआई को इस बात का भरोसा दिया है कि वह डेटा स्थानीयकरण नियमों का पूरी तरह पालन करेगी। डेटा स्थानीयकरण से जुड़े मुद्दों की वजह से ही कंपनी को भुगतान सेवा की अनुमति मिलने में देरी हो रही थी। सूत्र ने कहा, 'आवश्यक शर्तें पूरी करने की स्थिति में व्हाट्सऐप को पूर्ण रूप से भुगतान सेवा शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।' बिजनेस स्टैंडर्ड ने व्हाट्सऐप और एनपीसीआई से उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। पूर्ण रूप से सेवा शुरू करने पर व्हाट्सऐप देश में भुगतान सेवा खंड में सबसे बड़ी इकाई बन सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद और बैंक का बुनियादी ढांचा बड़ी संख्या में होने वाले संभावित लेनदेन का बोझ झेलने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार इसी वजह से व्हाट्सऐप को यह सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए कहा गया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर आधारित व्हाट्सऐप पे दूसरे ऐप से अलग है। एनपीसीआई द्वारा तैयार यूपीआई बैंक खाताधारकों को बिना नेट बैंकिंग, यूजर आईडी या पासवर्ड के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रकम भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। फिलहाल भारत में गूगल पे सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला यूपीआई ऐप है। इसके बाद फोनपे, पेटीएम और एनपीसीआई द्वारा विकसित भीम का भी इस्तेमाल होता है। व्हाट्सऐप ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ भुगतान सेवा का प्रयोग शुरू किया था।

ऐसा समझा जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर में व्हाट्सऐप पे की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई थी। संभवत: आरबीआई ने इस ऑडिट की अनुमति दी थी। व्हाट्सऐप को डेटा प्रसंस्करण अनुपालन से जुड़े मुद्दों का भी सामना करना पड़ा था।

बड़ी तादाद में लोगों तक व्हाट्सऐप की भुगतान सेवा देने से व्हाट्सऐप पे गूगल पे, वॉलमार्ट नियंत्रित फोनपे, एमेजॉन पे और अलीबाबा की पेटीएम को सीधी टक्कर देगी। भारत में डिजिटल भुगतान खंड में बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा जमाने के लिए इन कंपनियों में पहले से ही होड़ चल रही है।

खबरों के अनुसार पिछले साल मई तक गूगल पे के जरिये 24 करोड़ यूपीआई लेनदेन हुए, जबकि फोनपे और पेटीएम के मामले में यह संख्या क्रमश: 23 करोड़ और 20 करोड़ रही। पिछले सप्ताह फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वह अगले छह महीनों में कई देशों में व्हाट्सऐप पे भुगतान सेवा शुरू करना चाहते हैं।

भुगतान सेवा खंड में होड़!

- जनवरी 2020 में यूपीआई लेनदेन की संख्या रही 130.50 करोड़
- जनवरी 2020 तक यूपीआई के जरिये 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन
- गूगल पे के 6.7 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता
- फोनपे के 5.5 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता

- भारत में व्हाट्सऐप के 40 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता

मुख्य डिजिटल भुगतान इकाइयों में गूगल पे, फोनपे, पेटीएम और भीम शामिल

एलआईसी का नहीं होगा निजीकरण

हंसिनी कार्तिक और अभिजित लेले
मुंबई, 7 फरवरी

भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के चेयरमैन एम आर कुमार ने आज कहा कि कंपनी को सूचीबद्ध किए जाने के बाद कर्मचारियों सहित सभी पक्षों के हितों का संरक्षण किया जाएगा।

कुमार ने निजीकरण के सवाल को खारिज करते हुए कहा कि एलआईसी के आईपीओ से उसके कर्मचारियों, 2.9 करोड़ पॉलिसीधारकों और 12 लाख एजेंटों को फायदा होगा। इससे कंपनी में पारदर्शिता और कामकाज में सुधार में मदद मिलेगी।

ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलॉयीज एसोसिएशन के महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि एलआईसी की सूचीबद्धता के बाद काम का दबाव बढ़ने सहित काम के हालात को लेकर आशंकाएं हैं। फिलहाल कर्मचारी संघ पॉलिसीधारकों के संरक्षण और संपत्ति सृजन में एलआईसी के योगदान पर जोर दे रहा है।

कर्मचारी संगठनों ने एलआईसी के आईपीओ का विरोध करते हुए कहा कि इससे आम आदमी का विश्वास हिलेगा और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को कम लागत पर बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का एलआईसी का मूल उद्देश्य भटक जाएगा।

एम आर कुमार, एलआईसी, चेयरमैन

पिछले साल अक्टूबर में कुमार ने कहा था कि एलआईसी अभी आईपीओ के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आज उन्होंने कहा कि आईपीओ को लेकर कुछ समय से चर्चा चल रही थी लेकिन बजट में घोषणा से पहले कंपनी से कोई परामर्श नहीं किया गया। अब हम अगले सप्ताह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे और आईपीओ से पहले उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी लेंगे।

रक्षा प्रदर्शनी में बड़े समझौते

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 7 फरवरी

लखनऊ में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी (डिफेंस एक्सपो) के तीसरे दिन आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बन रहे रक्षा गलियारे के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), आईआईटी-कानपुर और टाटा टेक्नोलॉजी समेत 23 संस्थानों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रदर्शनी में शुक्रवार को विभिन्न हथियारों समेत 30 नए रक्षा उपकरणों पर से पर्दा हटाया गया। डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की 17 कंपनियों के साथ 15 नई तकनीकों के हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए।

- उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 23 समझौते के मसौदों पर हस्ताक्षर
- मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दावा, 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

राज्य के रक्षा गलियारे के लिए सलाहकार सेवाएं देने वाली इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के साथ भी समझौता हुआ। गलियारे में उपक्रम लगाने के लिए श्री रेफ्रिजरेशन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, लधानी समूह सहित कई अन्य कंपनियों के साथ समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50,000 करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनसे राज्य में 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा, 'पिछले 2 वर्षों के दौरान हम लोगों ने रक्षा गलियारे से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के साथ आयोजित करने का प्रयास किया था।' मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में ढाई लाख करोड़ से रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। इनके माध्यम से हमें 33 लाख से अधिक लोगों को सीधे-सीधे नौकरी और रोजगार से जोड़ने में मदद मिली है।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के साथ 23 समझौतों के मसौदों पर हस्ताक्षर करने वाले उद्यमी भारत के रक्षा अनुसंधान और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश के विकास में भी योगदान देंगे।

कोरोनावायरस से आईटी पर असर

नेहा अलावधी और देवाशिष महापात्र
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 7 फरवरी

चीन में नोवेल कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक वहां आने-जाने में लगी पाबंदी के कारण आने वाले हफ्तों में इन कंपनियों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, अब तक इन कंपनियों ने चीन में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे रखी है क्योंकि वहां नए साल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।

आईटी उद्योग के सूत्रों के मुताबिक चीन में भारतीय कपंनियों ने बड़ी संख्या में लोगों को काम पर रखा है। वहां उनके कर्मचारियों की संख्या 22,000 से अधिक है। इनमें स्थानीय लोगों के अलावा भारतीय शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चीन में 4,000 से अधिक कर्मचारी हैं जबकि इन्फोसिस और विप्रो के कर्मचारियों की संख्या 2,000 से अधिक है।

...कारोबार पर मार

- चीन में भारतीय आईटी कंपनियों के हैं करीब 22,000 कर्मचारी, इनमें स्थानीय एवं भारतीय कर्मचारी दोनों शामिल
- वुहान या इसके इर्द-गिर्द काम करने वाले पेशेवर की तादाद कम
- भारत के आईटी निर्यात में एशिया का योगदान करीब 8 प्रतिशत, चीन का इसमें ज्यादातर योगदान

सॉफ्टवेयर सर्विस उद्योग की संस्था नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) अपने सलाहकारों को चीन भेज रही है और वीचैट पर बनाए गए ग्रुपों के जरिये सदस्य कंपनियों के कर्मचारियों के साथ संपर्क में है। सदस्य कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के साथ जुड़े रहने के लिए वीचैट ग्रुप बनाए हैं।

नैसकॉम के ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट में वरिष्ठ निदेशक गगन सबरवाल ने कहा, 'लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है और बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने को कहा गया है। कोरोनावायरस का प्रकोप चीनी नववर्ष के वक्त फैला है, इसलिए वहां हर किसी ने अपनी छुट्टी बढ़ा ली है। 10 फरवरी को ऑफिस खुलेंगे और उसके बाद ही स्थिति की समीक्षा की जाएगी।' उन्होंने कहा कि अब तक किसी कर्मचारी के वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट नहीं है लेकिन सदस्य कंपनियों ने फेस मास्क का अनुरोध किया है। वायरस का संक्रमण शुरू होने के बाद से वहां फेस मास्क की कमी हो गई है।

विप्रो के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कंपनी ने अगले आदेश तक चीन, हॉन्ग कॉन्ग और मकाऊ आने-जाने पर पाबंदी लगा दी है। हमने खासकर चीन में अपने कर्मचारियों और हाल में वहां की यात्रा करने वाले कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हमने एक परामर्श भी जारी किया है जिसमें साफ-सफाई और एहतियाती उपायों की जानकारी दी गई है। ■ शेष पृष्ठ 14

संक्षेप में

डिबेंचर जारी कर रकम जुटाएगी मणप्पुरम फाइनैंस

मणप्पुरम फाइनैंस ने शुक्रवार को कहा कि वह डिबेंचर जारी कर 1,150 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाएगी। कंपनी ने बीएसई को बताया कि निदेशक मंडल की वित्तीय संसाधन व प्रबंधन समिति ने 7 फरवरी 2020 को हुई बैठक में रेटिंग प्राप्त, सुरक्षित व भुनाने योग्य गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर 1,150 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निदेशक मंडल की वित्तीय संसाधन एवं प्रबंधन समिति 14 फरवरी 2020 को बैठक करेगी। *भाषा*

स्पाइसजेट की सीओओ बनीं शिल्पा भाटिया

बजट विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने शिल्पा भाटिया को अपना नया मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीओओ) नियुक्त किया है। भाटिया कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह को रिपोर्ट करेंगी। विमानन कंपनी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाटिया राजस्व प्रबंधन, बिक्री और नेटवर्क योजना का कामकाज देखेंगी। *भाषा*

एनएचपीसी का शुद्ध लाभ दो गुना बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में दो गुना बढ़कर 639.13 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने के कारण कंपनी का लाभ बढ़ा है। एनएचपीसी ने शुक्रवार को कहा कि एक साल पहले 2018-19 की इसी तिमाही में उसे 287.96 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था। *भाषा*

पीएनबी: उधारी बढ़ेगी, सुधार होगा

बैंक ने जताई उम्मीद, एकीकृत बैंक की उधारी में होगी 8 से 10 फीसदी की वृद्धि

श्रीपाद ऑटे और अभिजित लेले
मुंबई, 7 फरवरी

नीरव मोदी घोखाधड़ी के बाद पिछले दो वर्षों के दौरान निवेशकों का भरोसा खोने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) वित्त वर्ष 2021 में एकीकृत बैंक के लिए उधारी में 8 से 10 फीसदी की वृद्धि के साथ वापसी करने की उम्मीद कर रहा है। बैंक उन 500 जगहों पर अपनी शाखाओं को युक्तिसंगत बनाएगा जहां पीएनबी और एकीकृत बैंकों (ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) की मौजूदगी एक ही बाजार में है।

पीएनबी के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी एसएस मल्लिकार्जुन राव ने आज दिसंबर 2019 तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद विश्लेषकों से बातचीत में कहा, 'हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी प्रतिष्ठा को थोड़ा झटका लगा है। लेकिन वह अब बीते दिनों की बात है क्योंकि बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है।' उन्होंने कहा, 'मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जून 2020 तक स्थिति बदल जाएगी। इसका कारण यह है कि हम मार्च 2020 तक उस विरासत को पूरी तरह अलग कर देंगे।'

एस्सार स्टील के समाधान से 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बाद बैंक की नजर संभवत: नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के उन 17 मामलों पर रहेगी जिनसे मार्च तिमाही में 8,700 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं। इससे वसूली की रकम बढ़कर 2,450 करोड़ रुपये हो जाएगी और पीएनबी के लिए 1,300 से 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दो बड़े एनपीए खाते- भूषण पावर ऐंड स्टील (3,781 करोड़ रुपये बकाया) और एयरसेल-डिशनेट वायरलेस (2,863 करोड़ रुपये बकाया)- का निपटान मार्च तक होने की उम्मीद है।

हालांकि कृषि और एमएसएमई पोटफोलियो पर अगली कुछ तिमाहियों तक दबाव बरकरार रहेगा जहां अगली दो तिमाहियों के दौरान फंसे कर्ज में 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये जाने की आशंका है। यहां तक कि तीसरी तिमाही के दौरान पीएनबी के कुल फंसे कर्ज में इन दो श्रेणियों में करीब 50 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। निगरानी वाले कुल करीब 4,900 करोड़ रुपये के डूबते कर्ज में से 2,900 करोड़ रुपये कॉरपोरेट श्रेणी से जबकि 2,000 करोड़ रुपये खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई श्रेणी से हैं।

राव को उम्मीद है कि पीएनबी के क्रेडिट की रफ्तार मार्च 2019 की तिमाही में सामान्य यानी करीब 4 फीसदी रहेगी, लेकिन वित्त वर्ष 2021 में यह सुधरकर 8-10 फीसदी पर पहुंच जाएगा। यह विलय के बाद बनने वाली इकाई के लिए है। खुदरा की रफ्तार करीब 20 फीसदी मानी गई है। वास्तव में बैंक नकद आरक्षित अनुपात में छूट का फायदा उठाएगी, जिसकी घोषणा आरबीआई ने की है और बैंक इसका इस्तेमाल अगले छह महीने में खुदरा पोर्टफोलियो में इजाफे में करेगा।

14 फरवरी को पीएनबी के बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें एकीकरण पर हुए काम की समीक्षा की जाएगी। विलय के बाद बनने वाली इकाई के रियल एस्टेट (इमारत व प्लॉट) के मुद्रीकरण के लिए अप्रैल में योजना को अंतिम रूप देगा। विलय की पूरी प्रक्रिया मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी।

प्रस्तावित इकाई की 500 अतिरिक्त शाखाओं की पहचान की गई है, जिसे बंद किया जाएगा, लेकिन बाद में दूसरी जगह खोली जाएगी और इस तरह से कुल शाखाओं की संख्या 11,500 होगी। राव ने यह भी कहा कि विलय के बाद बनने वाली इकाई अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इक्विटी पूंजी बाजार से जुटाने पर विचार करेगी। यह क्यूआईपी या एफपीओ आदि के जरिए हो सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। उनके मुताबिक, अभी पूंजी पर्याप्तता सहज स्थिति में है। अभी पीएनबी हाउसिंग में बैंक की पूरी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं है।

वित्तीय प्रदर्शन

- मार्च तिमाही में 2,450 करोड़ रुपये की रिकवरी की उम्मीद
- कृषि व एमएसएमई क्षेत्र से छह महीने में 5,000 करोड़ रुपये एनपीए में गए
- विलय की प्रक्रिया मार्च 2021 तक पूरी होगी
- खुदरा उधारी की रफ्तार वित्त वर्ष 2021 में 20 फीसदी होगी
- विलय के बाद बनने वाली इकाई की शाखाएं 11,500 होगी
- अगले वित्त वर्ष तक परिसंपत्ति गुणवत्ता होगी बेहतर, इक्विटी पेशकश दिसंबर तक

चॉकलेट बाजार में पैठ बढ़ाएगी आईटीसी

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 7 फरवरी

अपने चॉकलेट कारोबार की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से आईटीसी देश के शीर्ष छह महानगरों में जमीन तैयार कर रही है और 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रवेश करने की रणनीति बना रही है ताकि वह खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक चॉकलेट कंपनी के तौर पर स्थापित कर सके। कोलकाता के इस कारोबारी समूह ने अपने एफएमसीजी कारोबार से 1 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का कहना है कि इस लक्ष्य का 60 से 70 फीसदी हिस्सा फूड कारोबार से आएगा जिसमें चॉकलेट शीर्ष पांच श्रेणियों में शामिल होगा।

आईटीसी के मुख्य परिचालन अधिकारी (चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी, कॉफी एवं नई श्रेणियां, फूड) अनुज रुस्तगी ने कहा, 'हमने जिन श्रेणियों में प्रवेश किया है उनमें से सभी में अग्रणी हैं। हमारा उद्देश्य अगले एक दशक में खुद को चॉकलेट श्रेणी में अग्रणी बनाना है।' करीब 11,000 करोड़ रुपये के चॉकलेट बाजार में मोंडलीज 60 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। उसके बाद नेस्ले और फेरेरो का स्थान है।

आईटीसी पहले अपने मौजूदा बाजारों में गहरी पैठ बनाने के लिए नवाचार और विस्तार पर निवेश कर रही है। इन बाजारों में बेंगलूरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद शामिल हैं। इसके बाद कंपनी अन्य शहरों एवं कस्बों की ओर रुख करेगी। रुस्तगी ने कहा कि शीर्ष महानगरों में चॉकलेट खरीदारों की तादाद काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, बेंगलूरु बाजार से आने वाली मांग शेष कर्नाटक से आने वाली मांग के बराबर है। इसलिए कंपनी पहले इन केंद्रों पर बड़ा दांव लगाना और उसके बाद अन्य शहरों की ओर रुख करना चाहती है।

आईटीसी मॉल में किऑस्क स्थापित कर रही है ताकि चॉकलेट श्रेणी में अपनी पहुंच बढ़ाई जा सके। फिलहाल कंपनी के चॉकलेट केवल उसके बुटीक होटलों में ही उपलब्ध हैं। कंपनी लक्जरी श्रेणी में विस्तार के लिए हवाई अड्डों पर भी किऑस्क मॉडल अपनाने की योजना बना रही है।

कंपनी चॉकलेट बाजार में अपनी खास पहचान बनाने के लिए नवाचार पर जोर दे रही है। इसलिए डार्क, मिल्क और व्हाइट चॉकलेट के अलावा उसने प्रीमियम श्रेणी में रुबी चॉकलेट के तौर पर चौथे वेरिएंट को भी उतारा है। इसे फलों के हल्के स्वाद के साथ गुलाबी रंग में उतारा गया है। रुस्तगी ने कहा, 'हम मी टू उत्पाद को नहीं लाना चाहते हैं लेकिन हमारी पेशकश अनोखी होगी।'

आईटीसी ने 2018 में 70 से 200 रुपये कीमत दायरे के साथ आम लोगों के प्रीमियम चॉकलेट बाजार में कदम रखा था। कंपनी अब बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कम कीमत वाले उत्पाद लाने की भी योजना बना रही है। अपने हरिद्वारा संयंत्र के अलावा कंपनी ने भविष्य के लिए कई जगहों की पहचान की है ताकि वृद्धि को रफ्तार दी जा सके। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आपूर्ति शृंखला में भी निवेश कर रही है।

चॉकलेट का बाजार

भारत में चॉकलेट बाजार का आकार: **11,000** करोड़ रुपये
वृद्धि: साल दर साल **13** फीसदी
2019-20 में सीएजीआर की उम्मीद: **10** फीसदी

शीर्ष कंपनियां (राजस्व के लिहाज से)
मोंडलीज: **6,746** करोड़ रुपये
फेरेरो: **1,473** करोड़ रुपये
नेस्ले: **1,400** करोड़ रुपये
स्रोत: कंपनी वेबसाइट

कॉरपोरेशन बैंक का लाभ 7 गुना

एजेंसियां
मुंबई, 7 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र के कॉरपोरेशन बैंक ने दिसंबर 2019 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 420.83 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में सात गुना है। डूबे कर्ज के लिए प्रावधान बढ़ने के बावजूद ऊंची ब्याज आय की वजह से बैंक का लाभ बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 59.94 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी आय बढ़कर 6,051.93 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,112.29 करोड़ रुपये रही थी। एकल आधार पर तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध लाभ बढ़कर 420.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 60.53 करोड़ रुपये था। हालांकि, बैंक का डूबे कर्ज का अनुपात एक साल पहले की तुलना में नीचे आया है लेकिन यह अब भी उच्च स्तर पर है।

कुल मिलाकर तिमाही के दौरान बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 19,557.16 करोड़ रुपये रहीं जो इससे पिछले साल की समान तिमाही में 21,921.42 करोड़ रुपये थीं। समीक्षाधीन तिमाही में बैंक का शुद्ध एनपीए घटकर 6,321.81 करोड़ रुपये पर आ गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,521.22 करोड़ रुपये था। तिमाही के दौरान बैंक का डूबे कर्ज के लिए प्रावधान 1,300.35 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 842.27 करोड़ रुपये था।

एनटीपीसी का शुद्ध मुनाफा 23 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
नई दिल्ली/मुंबई, 7 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 23 फीसदी बढ़कर 3,197.93 करोड़ रुपये हो गया। मुख्य रूप से आय बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है।

एनटीपीसी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 2,608.18 करोड़ रुपये था। बयान के अनुसार कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 25,953.09 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 25,677.09 करोड़ रुपये थी। एनटीपीसी का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से दिसंबर अवधि में बढ़कर 9,446.93 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 7,774.42 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2018-19 में 12,633.45 करोड़ रुपये था।

इंडिया सीमेंट्स को 5.37 करोड़ रुपये का नुकसान

इंडिया सीमेंट्स ने दिसंबर 2019 में समाप्त तीसरी तिमाही में एकल आधार पर 5.37 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया जबकि पिछले साल की समान अवधि में उसे 3.13 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। कंपनी की कुल आय इस अवधि में 1,194 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,248 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी का एबिटा 132 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 139 करोड़ रुपये रहा था। कुल लागत घटकर 1,204 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,317 करोड़ रुपये रही थी।

अर्थव्यवस्था में मंदी और दक्षिण में सीमेंट की कमजोर मांग से कीमत पर दबाव बना रहा। तीसरी तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन पर इनका असर रहा, जिसके परिणामस्वरूप करीब 19 तिमाहियों के बाद कंपनी ने मामूली नुकसान दर्ज किया। उत्तर, पश्चिम व पूर्वी भारत में सीमेंट उद्योग ने प्रगति की, लेकिन 9 महीने की अवधि व तीसरी तिमाही में दक्षिण भारत में क्रमश: सुस्त रही।

कंपनी के वाइस चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने कहा कि तिमाही के दौरान संयंत्र से शुद्ध प्राप्तियों में 150 रुपये प्रति टन से अधिक की कमी आई जिससे एबिटा को 42 करोड़ रुपये से अधिक का झटका लगा। मार्जिन को प्रभावित करने वाला यह एकमात्र कारक रहा। तीसरी तिमाही के दौरान संयंत्र से शुद्ध प्राप्तियां घटकर 3,342 रुपये प्रति टन रह गई जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,308 रुपये प्रति टन थी।

एनसीसी का कर पूर्व लाभ घटा

हैदराबाद की निर्माण कंपनी एनसीसी लिमिटेड का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) दिसंबर 2019 में समाप्त तिमाही के दौरान 75 फीसदी घटकर 64.83 करोड़ रुपये रह गया। जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह आंकड़ा 256.30 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने कहा कि राजस्व में गिरावट से मुनाफे को झटका लगा। तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय 33.16 फीसदी घटकर 2,282.98 करोड़ रुपये रह गई जो पिछले साल की समान अवधि में 3,157.84 करोड़ रुपये रही थी। तिमाही के दौरान कंपनी का खर्च भी 29.75 फीसदी घटकर 2,218.47 करोड़ रुपये रह गया जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,157.84 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि क्रमिक आधार पर कंपनी के राजस्व में 14 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

कंपनी परिणाम

एल्केम का लाभ 90 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
नई दिल्ली/मुंबई, 7 फरवरी

औषधि कंपनी एल्केम लैबोरेटरीज का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 89.80 फीसदी बढ़कर 389.96 करोड़ रुपये रहा। एल्केम ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी को 205.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की एकीकृत आय चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 2,181.84 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1,926.32 करोड़ रुपये थी। निदेशक मंडल ने 2019-20 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर 22 रुपये प्रति इक्विटी का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल बासुदेव एन सिंह को कार्यकारी चेयरमैन फिर से नियुक्त करने और पारितोषिक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए की गई है।

वोल्टास का लाभ बढ़ा

एयरकंडीशनर बनाने वाली टाटा समूह की कंपनी वोल्टास का एकीकृत शुद्ध दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही में 12.64 फीसदी बढ़कर 87.95 करोड़ रुपये रहा। वोल्टास ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी को 78.08 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। कंपनी की परिचालन आय 2019-20 की तीसरी तिमाही में 1,492.51 करोड़ रुपये रही।

विदेशी निवेशक आईएफएससी में कर अनिश्चितता से निराश

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 7 फरवरी

गुजरात इंटरनैशनल फिन-टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में मौजूद एक्सचेंजों पर रुपया बॉन्डों में कारोबार करने वाले विदेशी निवेशकों को दी गई कर रियायत से अनिश्चितता पैदा हुई है।

आईएफएससी में बॉन्डों की सूचीबद्धता बढ़ाने के प्रयास में बजट में रुपया-आधारित बॉन्डों में निवेश पर प्राप्त ब्याज के लिए विदहोल्डिंग टैक्स में कमी की गई। इस कर को 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है। हालांकि इन निवेशकों के लिए कुल कर दरें 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि वैश्विक निवेशकों को रिटर्न फाइल करना होगा और आयकर कानूनों का पालन करते हुए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर चुकाना होगा। इससे अनुपालन लागत बढ़ जाएगी और जांच सख्त हो जाएगी, क्योंकि निवेशकों को संबद्ध लेनदेन का विवरण, कर पहचान संख्या (टीआईएन) और अन्य जानकारियां देनी होंगी।

ईवाई इंडिया में पार्टनर अनीश ठाकर ने कहा, 'आईएफएससी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध डेट योजनाओं में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को 4 प्रतिशत के कम विदहोल्डिंग टैक्स का सामना करना होगा। हालांकि इस आय पर कर की दर 5 प्रतिशत बनी रहेगी। इससे निवेशकों द्वारा कर भुगतान और रिटर्न फाइल के संदर्भ में अतिरिक्त अनुपालन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।'

आईएफएससी में ट्रेडिंग के लिए रियायती कर दरें 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी और 30 जून, 2023 तक वैध रहेंगी। विदहोल्डिंग टैक्स स्रोत के तौर काटे गए कर के समान है, जिसमें आय मुहैया कराने वाला आय प्राप्त करने वाले को भुगतान से पहले कर काटने के लिए जिम्मेदार होता है।

एक व्यक्ति ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'सरकार जो करना चाहती है और जो कर रही है, उसके बीच बड़ा अंतर दिख रहा है। आईएफएससी एक ऐसा ऑफशोर क्षेत्राधिकार है जिसे एक नियामक और कर अनुपालन जोन के तौर पर प्रवर्तित किया गया है।'

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर राजेश गांधी का मानना है कि रियायती दर से कंपनियों को गिफ्ट एक्सचेंज पर अपने बॉन्ड सूचीबद्ध कराने में मदद मिल सकेगी। उनका मानना है कि सरकार गिफ्ट में सूचीबद्धता बढ़ाने के लिए आंशिक कर राहत के बजाय, कम से कम शुरुआती वर्षों में संपूर्ण कर छूट पर विचार कर सकती थी। उन्होंने कहा, 'ऊंची कर दर एक बड़ी विसंगति है और उम्मीद है कि इस समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा।'

डेट निवेशकों के लिए रियायती दर के अलावा, इस साल के बजट में इस वित्तीय हब में अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया। इससे वैश्विक बाजार कारोबारियों को कारोबार का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और इस एक्सचेंज का इस्तेमाल स्वर्ण आयात के लिए भी किया जा सकेगा।

आईएफएससी ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान निवेशकों को कई तरह की रियायत मुहैया कराई हैं। इनमें प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भुगतान, जिंस लेनदेन कर और स्टांप शुल्क से छूट के साथ साथ आईएफएससी एक्सचेंज पर डेरिवेटिव्स, बॉन्डों, वैश्विक डिपोजिटरी रिसीट और रुपया बॉन्डों में लेनदेन पर पूंजीगत लाभ कर से छूट शामिल हैं।

गिफ्ट सिटी में कारोबार

- रुपया-आधारित बॉन्डों में निवेश पर विदहोल्डिंग टैक्स घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है
- विदेशी निवेशकों के लिए कुल कर दरें 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई हैं
- उद्योग ने ऐसे बॉन्डों पर पूरी कर छूट दिए जाने की मांग की थी
- भारत में ऐसे बॉन्डों की रियायती कर व्यवस्था में अलग कर दरें नहीं हैं

इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार होगी तेज

ऋषभ कृष्ण सक्सेना
नई दिल्ली, 7 फरवरी

- बजट में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन पर आयात शुल्क 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है
- पुर्जों में आने वाले (सीकेडी) इलेक्ट्रिक वाहन पर शुल्क 10 के बजाय 15 फीसदी करने की घोषणा हुई है

भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार को लेकर नामी कंपनियां बेशक अभी थोड़ी हिचक रही हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां तेजी से अपने काम में लगी हैं और बजट में ई-वाहन पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला उन्हें पसंद आया है। बजट में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन पर आयात शुल्क 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। पुर्जों में आने वाले (सीकेडी) इलेक्ट्रिक वाहन पर शुल्क 10 के बजाय 15 फीसदी करने की घोषणा हुई है।

देश के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिक बस चला चुकी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को यह पहल देसी कंपनियों और 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिहाज से एकदम अनुकूल लगती है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एन नागा सत्यम ने कहा के चीनी कंपनियों के हमले से बचने और भारत में ही ई-वाहन की महारत तैयार करने के लिहाज से यह बेहद अहम कदम है। उन्होंने कहा, बाहर से तैयार गाड़ी उतारना आसान काम है, लेकिन उससे देश में तकनीकी कौशल तैयार नहीं होता। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को वाकई रफ्तार देनी है तो ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे।

ई-बस के विकास में 600 करोड़ रुपये लगाने वाली ग्रीनटेक रोहतांग जैसे दुर्गम इलाके समेत देश भर में 270 से अधिक ई-बस बेच चुकी कंपनी को 2020 में 700 नई ई-बस बेचने की उम्मीद है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और सूरत प्रशासन समेत कई निगमों से उसकी बात चल रही है। अपने स्थापित वाहन ट्रैवलर का इलेक्ट्रिक संस्करण उतारने वाली पुणे की कंपनी फोर्स मोटर्स भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ा रही है और उसे लगता है कि फेम 2 कार्यक्रम के साथ आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी था। जर्मन कंपनी से तकनीकी साझेदारी में बना कंपनी का ई-ट्रैवलर बैटरी के अलावा पूरी तरह भारत निर्मित है। कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रसन्न फिरोदिया ने कहा कि भारत में ई-वाहन का अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) बढ़ाने के लिए सरकार के ऐसे कदम जरूरी हैं क्योंकि विदेश से तैयार गाड़ी लाकर बेचना आसान है मगर निवेश और कौशल के लिहाज से देश को इससे कोई फायदा नहीं होगा।

कंपनी ने करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश कर शेयर्ड मोबिलिटी का अपना नया प्लेटफॉर्म टी1एन तैयार किया है और इस पर भी ई-ट्रैवलर बनाया जाएगा। फिरोदिया ने बताया कि फीडर वाहनों के तौर पर शहर में इस्तेमाल होने वाले ई-ट्रैवलर के लिए राज्य सरकारों और ओला जैसे फ्लीट ऑपरेटरों से बातचीत की जाएगी।

हालांकि कंपनियों को लगता है कि चार्जिंग ढांचा तैयार करने में सरकार कुछ सुस्त है। फिरोदिया कहते हैं कि लंबी दूरी के वाहन तभी चलेंगे, जब चार्जिंग स्टेशन दिए जाएंगे क्योंकि कंपनियां वाहन बना सकती हैं, चार्जिंग ढांचा नहीं। हालांकि ग्रीनटेक ने अपनी बसों के लिए चार्जिंग डिपो बनाए हैं, जहां से पूरी तरह चार्ज होने के बाद ही बस किसी शहर के लिए रवाना होती है।

चीन से बाहर आपूर्ति के विकल्प पर विचार कर रही सुजूकी

रॉयटर्स
टोक्यो, 7 फरवरी

सुजूकी मोटर कॉर्प ने शुक्रवार को कहा कि वह चीन से बाहर वाहनों के कलपुर्जे की आपूर्ति का विकल्प तलाश रही है क्योंकि उस देश में कोरोनावायरस के प्रसार से उसके सबसे बड़े बाजार भारत में वाहनों के उत्पादन में अवरोध पैदा होने की आशंका है। कोरोनावायरस के प्रसार से करीब 640 लोगों की जान जा चुकी है।

उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी टोयोटा मोटर कॉर्प ने शुक्रवार को कहा कि चीन में उसके संयंत्रों में उत्पादन 16 फरवरी तक स्थगित रहेगा, वहीं फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स एनवी ने कहा कि अगर चीन से कलपुर्जे की आपूर्ति जल्द बहाल नहीं होती तो यूरोपीय संयंत्र दो हफ्ते के भीतर बंद हो सकता है।

सुजूकी चीन में किसी कार का उत्पादन व बिक्री नहीं करती, लेकिन अपने भारतीय संयंत्रों के लिए वहां से कुछ कलपुर्जे खरीदती है। भारतीय बाजार में सुजूकी का अपनी स्थानीय इकाई मारुति सुजूकी इंडिया के जरिये यात्री वाहन बाजार के आधे पर नियंत्रण है।

कंपनी के प्रबंध अधिकारी मसाहिको नागाओ ने कहा, उसका वैश्विक उत्पादन अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन सुजूकी अन्य इलाकों से मेड इन चाइना कार कलपुर्जे की आपूर्ति की संभावना तलाश रही है। जापान की चौथी सबसे बड़ी वाहन निर्माता ने कहा कि दिसंबर तिमाही में उसका परिचालन लाभ 11 फीसदी घटकर 51.8 अरब येन रह गया, जो मार्च 2016 की तिमाही के बाद का सबसे निचला स्तर है और नौ विश्लेषकों के 58.4 अरब येन के औसत अनुमान से भी कम है।

बीएस बातचीत

मार्च 2021 तक प्रवर्तकों के गिरवी शेयर छुड़ा लेंगे

सीमेंट कारोबार बेचने के लिए नूवोको विस्टास संग करार की घोषणा के एक दिन बाद इमामी समूह के निदेशक **मोहन गोयनका** ने **ईशिता आयान दत्त** और **अभिषेक रक्षित** को दिए साक्षात्कार में कहा कि कंपनी का ध्यान कर्ज मुक्त बनने पर है और इस दिशा में जो भी करने की दरकार होगी, किया जाएगा। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

इमामी लिमिटेड में प्रवर्तकों के कितने गिरवी शेयर हैं और कब यह नीचे आएगा?
अभी गिरवी शेयर करीब 70 फीसदी है। नियामकीय मंजूरी के बाद जब हमें मई-जून तक करीब 3,300 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह 100 फीसदी नकद सौदा है। शेयर के बदले प्रवर्तकों का कर्ज 3,000 करोड़ रुपये है। हमें कुल 3,300 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन हमें कर व अन्य जरूरत के लिए मोटे तौर पर 800 करोड़ रुपये अलग रखने होंगे। ऐसे में 500-600 करोड़ रुपये कर्ज रह जाएगा। अन्यथा हम पूरी रकम चुका देते। ऐसे में गिरवी शेयर 15-18 फीसदी के बीच होगी। इसके अलावा हम 8 फीसदी गिरवी खरीदार नूवोको को दे रहे हैं। इस तरह से कुल गिरवी करीब 25 फीसदी होगी।

क्या इस लेनदेन के लिए नूवोको को 8 फीसदी गिरवी वास्तव में दिया जाएगा?
जांच-परख (ड्यू डिलिजेंस) के समय कुछ अवलोकन किया गया था, उसके आधार पर उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी थी। हमारे पास रकम घटाने का विकल्प था। लेकिन हमने इमामी लिमिटेड के शेयर सिक्योरिटी के तौर पर देने का फैसला लिया। जब नियामकीय मंजूरी मिल जाएगी तो हमें भरोसा है कि हम इसे मार्च 2021 तक छुड़ा लेंगे। यह काम इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मामला विचाराधीन है।

क्या अभी कोई मामला चल रहा है?
हां, हमें वकीलों से कुछ स्पष्टीकरण चाहिए था, लेकिन हम सौदा पूरा करना चाहते थे। ऐसे में हमने कहा कि हमें इसका निपटान करने दीजिये और जैसे-जैसे प्रगति होगी, हम अपने शेयर मुक्त करा लेंगे।

क्या आपको लगता है कि इमामी समूह ने कारोबार काफी ज्यादा फैला लिया था?
कारोबारी नजरिये से देखें तो हमने पिछले चार साल में सीमेंट में करीब 1,000 करोड़ रुपये निवेश किया और अगर हम 1,000 करोड़ रुपये पर 2,500 करोड़ रुपये हासिल कर रहे हैं तो क्या यह सौदा बुरा है ? हम और कितने रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं ?

आने वाले समय में समूह का ध्यान किन चीजों पर होगा?
प्रवर्तक इकाई के तौर पर हम अपना कर्ज शून्य पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में जो भी करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं। मार्च 2021 तक हमारे प्रवर्तकों के गिरवी शेयर शून्य पर आ जाएंगे।

कारोबारी क्षेत्र के लिहाज से समूह का किस पर ध्यान होगा?
अस्पताल, हम इसका विनिवेश करना चाहते हैं। एफएमसीजी खाद्य तेल, पेपर और रियल एस्टेट पर हमारा ध्यान रहेगा।

क्या आप अस्पताल कारोबार से पूरी तरह निकलेंगे या भुवनेश्वर अस्पताल की बिक्री एकबारगी हो जाएगी?
हम पूरी तरह निकलने पर विचार कर रहे हैं। कर्ज को शून्य पर ले जाने के लिए जिन चीजों से मदद मिलेगी, हम करेंगे।

इमामी का शुद्ध लाभ 5 फीसदी बढ़ा

घरेलू एफएमसीजी कंपनी इमामी लिमिटेड ने बाजार के अनुमानों खरा उतरते हुए 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 813 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर राजस्व वृद्धि दर्ज की। जबकि उसका कर पूर्व लाभ 5 फीसदी बढ़कर 184 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ये आंकड़े क्रमश: 811 करोड़ रुपये और 176 करोड़ रुपये रहे थे। तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ भी 5 फीसदी बढ़कर 144 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 138 करोड़ रुपये रहा था। बीएस

जांच के कारण एसबीआई काड्र्स आईपीओ में हुई देर

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 7 फरवरी

करीब एक दशक पहले जारी नियामकीय दिशानिर्देश से बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों में से एक में अप्रत्याशित देरी हो रही है। बाजार नियामक सेबी ने एसबीआई काड्र्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज (भारतीय स्टेट बैंक की क्रेडिट कार्ड इकाई) की विवरणिका के मसौदे को अभी मंजूरी नहीं दी है।

पेशकश दस्तावेज नवंबर में नियामक के पास जमा कराए गए थे और कंपनी ने जनवरी के शुरू में रोडशो पूरा कर लिया और कंपनी को उम्मीद थी कि उसी महीने वह बाजार में आईपीओ उतार देगी।

हालांकि समूह कंपनी एसबीआई म्युचुअल फंड के खिलाफ जारी जांच के कारण नियामक ने शेयर बिक्री को स्थगित रखा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उस पर भेदिया कारोबार का आरोप है, जिसका विरोध कंपनी कर रही है। यह आरोप मणप्पुरम फाइनैंस के शेयर में ट्रेडिंग को लेकर है। एसबीआई एमएफ पांच परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में शामिल है जिसे सेबी ने पिछले साल कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह नोटिस कीमत संवेदनशील सूचनाओं का कथित इस्तेमाल मार्च 2013 में मणप्पुरम के शेयरों की ट्रेडिंग में किया गया। एसबीआई काड्र्स के पेशकश दस्तावेज में कहा गया है, समूह कंपनियों में से एक एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेबी ने जांच शुरू की है।

सेबी की तरफ से साल 2006 में जारी सामान्य आदेश के मुताबिक, पेशकश दस्तावेज के मसौदे पर नियामक का आकलन कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख या पेशकश दस्तावेज जमा कराए जाने की तारीख से 90 दिन तक स्थगित रखा जाएगा (जो भी बाद में हो)।

स्टेट बैंक ने घटाई जमा व उधारी दर

अभिजीत लेले
मुंबई, 7 फरवरी

देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने खुदरा और थोक सावधि जमाओं पर ब्याज दरों में 10 से लेकर 50 आधार अंकों की कटौती करने का फैसला किया है। नई दरें 10 फरवरी से लागू हो जाएंगी।

एसबीआई ने आज जारी एक बयान में नई जमा ब्याज दरों की घोषणा की। इसके साथ ही बैंक ने सभी अवधि वाले सीमांत लागत-आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में भी पांच आधार अंकों की कटौती की है। एक साल का एमसीएलआर 7.90 फीसदी से घटकर 7.85 फीसदी हो गया है। यह वित्त वर्ष 2019-20 में एमसीएलआर में की गई लगातार नौवीं कटौती है।

एसबीआई का फैसला

जनवरी-दिसंबर 2019 के 12 महीनों में बैंक का कुल कर्ज वितरण 6.8 फीसदी बढ़कर 23,01,669 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी में खुदरा एवं व्यक्तिगत ऋण का मुख्य योगदान रहा है जो 17.49 फीसदी दर से बढ़ा है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने पिछले महीने कहा था कि साल की शुरुआत में बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में उधारी में 10-12 फीसदी वृद्धि की संभावना जताई थी लेकिन कॉर्पोरेट ऋण की कमजोर मांग को देखते हुए 10 फीसदी के स्तर तक पहुंच पाना मुश्किल होगा।

एसबीआई ने अपने संसाधनों की स्थिति को देखते हुए यह तय किया है कि उसके पास अधिक तरलता होने से 2 करोड़ रुपये से कम राशि की खुदरा सावधि जमाओं और 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि की मोटी जमा पर ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। जमा पर ब्याज दरों में 0.1-0.5 फीसदी तक की कमी कर दी गई है। नई दरें अगले कामकाजी हफ्ते की शुरुआत से प्रभावी हो जाएंगी।

दरअसल बैंक के पास जनवरी-दिसंबर 2019 की अवधि में जमा 9.9 फीसदी बढ़कर 31,11,229 करोड़ रुपये जा पहुंचा। कम लागत वाली जमाओं का हिस्सा 51 आधार अंक की गिरावट के साथ 44.72 फीसदी हो गया जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 45.23 फीसदी रहा था।

फिर आएगा जमा-बीमा विधेयक

अरूप रायचौधरी
मुंबई, 7 फरवरी

सरकार वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक फिर से लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन समयसीमा अब तक तय नहीं हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यह जानकारी दी। एक उपबंध को लेकर आलोचना होने पर अगस्त 2018 में एफआरडीआई वापस ले लिया गया था जो बैंक विफलता के मामले में जमाकर्ताओं को जमानत देने के लिए बाध्य करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस समय जमा बीमा का दायरा केवल एक लाख रुपये था, इसलिए इस विधेयक बिल को लेकर काफी हो-हल्ला हुआ है। नए बजट में सरकार ने जमा बीमा का दायरा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों की मदद के लिए दिवाला कानून में भी बदलाव किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, 'एक बार यह (एफआरडीआई विधेयक) पेश किया गया था और कुछ कारणों से इसे वापस ले लिया गया था। हमने इस पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब पेश करूंगी।' सीतारमण ने कहा कि मुंबई की अपनी पिछली यात्रा में पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के साथ मुलाकात बहुत कष्टकारी थी। हालांकि वह जवाब नहीं देना चाहती थी कि क्या पांच लाख रुपये का जमा बीमा का लाभ पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को भी मिलेगा। साथ ही यह प्रस्ताव अब भी संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। सीतारमण मुंबई में वित्त मंत्रालय के उन सभी सचिवों के साथ थीं। जिन्होंने बजट को लोगों तक पहुंचाने में सरकार की पहल के रूप में किम किया है। यह टीम बजट पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शनिवार को चेन्नई और रविवार को कोलकाता सहित विभिन्न शहरों की यात्रा करेगी। मुंबई में वित्त मंत्री और उनकी बजट टीम ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, फंड प्रबंधकों और पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ मुलाकात की।

मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में वित्त एवं कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ में हैं सचिव और वरिष्ठ अधिकारी *फोटो-पीटीआई*

मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सीतारमण ने कहा कि वह इस बात का आकलन करेंगी कि उनकी नई व्यक्तिगत कर योजना को लोग किस प्रकार स्वीकार करेंगे और इस आकनल के आधार पर वह देखेंगी कि क्या यह छूट पूरी तरह से बंद कर दी जानी चाहिए। बजट में वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर के दो विकल्पों वाली संरचना बनाई। इसमें से विकल्प छूट के बिना लेकिन कम कर दर वाला है और छूट के साथ दूसरा मौजूदा कर दरों वाला विकल्प है।

सीतारमण ने कहा कि आखिरकार हम भारत के लिए एक आयकर ढांचा तैयार करना चाहते हैं जो सरल होगा। दरें न्यूनतम हो जाएंगी जिससे लोगों को इनका अनुपालन करने में मदद मिलेगी। मैं किसी को विवश नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं एक विकल्प दे रही हूं। हम इस वर्ष देखेंगे कि कितने लोग इस ओर रुख करते हैं। वर्ष दौरान हम इसे समझेंगे और इसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं।

कर संरचना का बचाव करते हुए सीतारमण ने पिछले साल संवाद सत्र में कहा था कि जब सरकार ने भारतीय कंपनियों को एक समान कर संरचना की पेशकश की, तो उनमें से 90 प्रतिशत ने कम कर दर को स्वीकार किया था।

नए सिरे से तैयारी कर रही सरकार

- एफआरडीआई विधेयक फिर से लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन समयसीमा अब तक तय नहीं
- एक उपबंध को लेकर आलोचना होने पर अगस्त 2018 में एफआरडीआई वापस ले लिया गया था
- वित्त मंत्री को भरोसा है कि 80 प्रतिशत करदाता बजट में पेश की गई नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे

जीवन सुगमता, निकाय प्रदर्शन सूचकांक आया

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 7 फरवरी

देश के प्रमुख शहरों में नागरिक सुविधाएं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से केंद्र सरकार ने आज दो सूचकांक पेश किए। 100 से ज्यादा शहरों में नागरिक सुविधाओं और जीवन स्तर के आंकड़ों के साथ सूचकांक में प्रत्येक शहर का विस्तृत आंकड़ा होगा। इससे सरकार को भविष्य की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जीवन सुगमता सूचकांक (ईओएलआई) का मकसद भारत के शहरों के बारे में समग्र नजरिया प्रदान करना है, जिसमें स्थानीय नियाकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, प्रशासन की कुशलता, शहर में रहने की स्थिति के हिसाब से उन सेवाओं की प्रभावशीलता और उनके परिणामों पर नागरिकों की धारणा का ब्योरा होगा।

सूचकांक के अहम उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें साक्ष्य के आधार पर नीति बनाने के लिए सूचना एकत्र करना, टिकाऊ विकास के उद्देश्यों के साथ विकास के व्यापक परिणाम हासिल करने के लिए कार्यवाई को प्रोत्साहित करना, विभिन्न शहरी नीतियों व कार्यक्रमों से हासिल परिणामों के बारे में जानकारी व उसकी तुलना और शहर के प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं पर नागरिकों के विचार लेकर उनकी धारणा के बारे में जानना शामिल है।

2019 में नागरिकों के जीवन सुगमता का आकलन तीन प्रमुख आधारों, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक सक्षमतता और टिकाऊपन के आधार पर होगा, जिन्हें आगे 50 संकेतकों के आधार पर 14 भागों में विभाजित किया गया है। इस तरह से ईओएलआई का पहला संस्करण 3 व्यापक मानकों के आधार पर नागरिकों की जीवन सुगमता के आकलन की सुविधा देगा।

इसमें अधिसूचित 100 स्मार्ट सिटी व 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 और शहरों को शामिल किया गया है, जिन पर विचार होगा। शहरों में पहले ही नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो विभिन्न विभागों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का प्रभार देखेंगे, जो शहरी स्थानीय निकायों के भीतर व उसके बाहर दोनों के ही आंकड़े होंगे। ये आंकड़े तैयार किए जाने के बाद इनका समर्थन करने वाले दस्तावेजों के साथ एक वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो खासकर इसी मकसद के लिए डिजाइन किया गया है।

निकाय प्रदर्शन सूचकांक (एमपीएआई) में नगर निकायों के प्रदर्शन का आकलन 5 आधारों पर होगा, जिनमें सेवा, वित्त, योजना, टेक्नोलॉजी और प्रशासन शामिल है। इसे आगे 20 सेक्टरों और 100 इंडिकेटरों में विभाजित किया जाएगा।

नोडल अधिकारियों की मदद के लिए मंत्रालय ने केंद्रीय सहायता कक्ष बनाया है, जिसका इस्तेमाल नोडल अधिकारी प्रक्रिया व संकेतकों से जुड़े मामलों में स्पष्टीकरण के लिए कर सकेंगे और सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा मंत्रालय ने 1 फरवरी से नागरिक धारणा सर्वे शुरू किया है, जिसमें नागरिकों से उनके शहर में जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी उनकी धारणा के बारे में सीधे जानकारी ली जाएगी। यह सर्वे सीधे बातचीत और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसका ईओएलआई में अधिभार 30 प्रतिशत होगा।

नई कवायद

- सरकार के मुताबिक जीवन सुगमता सूचकांक का मकसद भारत के शहरों के बारे में समग्र नजरिया प्रदान करना
- निकाय प्रदर्शन सूचकांक में नगर निकायों के प्रदर्शन का आकलन 5 आधारों पर होगा
- 100 से ज्यादा शहरों में नागरिक सुविधाओं, जीवन स्तर के आंकड़ों के साथ सूचकांक में प्रत्येक शहर का विस्तृत आंकड़ा होगा

बीएस बातचीत

जीएसटी कर ढांचे में फेरबदल में लगेगा वक्त : सीबीआईसी

तमाम बड़ी कंपनियां जीएसटी के पहले के उत्पाद शुल्क और सेवा कर के मामले में सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना से दूर रहीं। बजट तैयार किए जाने के वक्त केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कार्यकारी चेयरमैन रहे **जॉन जोसेफ** का कहना है कि कंपनियों को भरोसा है कि वे सरकार से न्यायालय में जीत जाएंगी। **दिलाशा सेठ** के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें फिलहाल राजस्व के हिसाब से नकारात्मक थीं, जिस पर मंत्रिसमूह द्वारा विचार किया जा रहा है, लेकिन इसे लागू करने में वक्त लगेगा। संपादित अंश...

सरकार ने सकल आयात मूल्य पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) में बढ़ोतरी न करके 5 प्रतिशत स्वास्थ्य उपकर क्यों लगाया है? क्या इससे ईलाज का खर्च बढ़ेगा?

मुझे ऐसा नहीं लगता। महज 5 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। सभी मेडिकल उपकरण भारत में विनिर्मित होंगे, जबकि आयातित उपकरण चीन के होते हैं। उपकर से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा सरकार को लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देने में मदद मिलेगी। मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत है और बीसीडी पर महज 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, जबकि हमें ज्यादा राजस्व की जरूरत है। ऐसे मे हमने सकल आयात पर इसे लगाने का फैसला किया है।

सीमा शुल्क में बढ़ोतरी से सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है?

हमने राजस्व बढ़ाने के मकसद से सीमा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है। इसे मेक इन इंडिया को समर्थन देने के लिए लगाया गया है। इसलिए हमने यह अनुमान नहीं लगाया है कि इससे कितना राजस्व मिलेगा।

हाल ही में उद्योग के साथ बातचीत में राजस्व सचिव एबी पांडेय ने जीएसटी ढांचे में 3 दरों की बात की थी। क्या 5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत ढांचे में से किसी को खत्म करने या 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत ढांचे को मिलाने की योजना है?

यह जीएसटी परिषद पर निर्भर होगा कि वह क्या करना चाहती है। अभी दरें राजस्व के हिसाब से नकारात्मक हैं, निरपेक्ष नहीं। दर के ढांचे को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है। मंत्रियों का एक समूह इस मसले पर विचार कर रहा है। वह रिपोर्ट देंगे और उस पर चर्चा होगी। ढांचे में फेरबदल में वक्त लगेगा और ऐसा कुछ तत्काल नहीं होने जा रहा है।

संशोधित अनुमान में लक्ष्य कम किए जाने के बावजूद अप्रत्यक्ष कर संग्रह अभी भी ज्यादा नजर आ रहा है?

मुझे नहीं लगता कि अनुमान बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि संग्रह 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये कम हो, लेकिन फरवरी में 1.1 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह की उम्मीद है और मार्च में इससे भी ज्यादा रहेगा। सबका विश्वास से हुआ संग्रह भी इसमें जुड़ेगा और उत्पाद शुल्क संग्रह भी भुगतान के रूप में फरवरी से आएगा।

हालांकि 1,90,000 करदाताओं ने सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना में आवेदन किया है, लेकिन बड़ी कंपनियां इससे दूर हैं। ऐसा क्यों?

बड़ी कंपनियों का मानना है कि वे बाहर लड़ाई लड़ सकती हैं। सरकार के मुकदमे जीतने की दर महज 10 प्रतिशत है, ऐसे में कंपनियां निश्चित रूप से सोचती हैं कि 30 प्रतिशत भुगतान क्यों किया जाए। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वे सोचती हैं कि जीतने के लिए यह बढ़िया मामला है। लेकिन योजना विभाग के लिए सफल रही है।

80 लोगों को नौकरी से निकालेगी मिंत्रा

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 7 फरवरी

वॉलमार्ट की ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा अपने गुरुग्राम कार्यालय के कर्मचारियों में कम से कम 3 प्रतिशत कटौती करने जा रही है। परिचालन को प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए कंपनी करीब 80 कर्मचारियों की छटनी करेगी। मिंत्रा में करीब 3,000 कर्मचारी हैं और यह छटनी बिजनेस ऑपरेशन, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी व मार्केटिंग सहित हर क्षेत्र में होनी है।

कर्मचारियों को भेजे गए ई मेल में मिंत्रा ने कहा कि वह अपने संसाधनों का एकीकरण कर रही है और परिचालन घटा रही है। ई मेल में लिखा गया है, 'परिणामस्वरूप हमारे कुछ मित्रों व सहकर्मियों की भूमिका पर असर पड़ेगा। हमने कुछ कड़े फैसले किए हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि हम उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सही दिशा में कदम उठा रहे हैं।' शुक्रवार को संपर्क किए जाने पर मिंत्रा के प्रमुख अमर नागरम ने कहा कि कंपनी मुआवजा पैकेज, बढ़े हुए स्वास्थ्य लाभों व आउटप्लेसमेंट सर्विसेज के माध्यम से इन कर्मचारियों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा, 'यह कठिन फैसला था, लेकिन हमारा मानना है कि यह कदम उचित था, जिससे तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में हमारे कारोबार का टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके।'

मेडिकल उपकरणों पर उपकर लगाए जाने से अमेरिका नाखुश

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 7 फरवरी

अमेरिका के वाणिज्य अधिकारी भारत द्वारा मेडिकल उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाने की कवायद से नाखुश हैं। भारत सरकार ने हाल ही में आयात पर अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकर लगा दिया है।

भारत ने कहा है कि वह कर वापस नहीं लेगा, वहीं सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर की अगले सप्ताह की शुरुआत में प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान बातचीत में अन्य छूट की पेशकश की जा सकती है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारत अभी भी कुछ खास ज्यादा दाम वाले सामान जैसे कोरोनरी स्टेंट पर कारोबारी मुनाफे की नीति को अनुमति देने पर विचार कर रहा है।

बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयातित मेडिकल उपकरणों पर 5 प्रतिशत स्वास्थ्य उपकर लगाने की घोषणा की थी। उद्योग के जानकारों का कहना है कि इस कदम से आयातित मेडिकल उपकरण मरीजों के लिए कम से कम तब तक के लिए महंगे हो जाएंगे, जब तक कि इनका घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता है। स्वास्थ्य उपकर मेडिकल उपकरणों के आयात पर लगाया जाएगा, सिर्फ उन उपकरणों को इससे छूट मिलेगी, जिन पर मूल सीमा शुल्क नहीं लगता है।

पिछले साल नवंबर में वाशिंगटन यात्रा के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एडवामेड (अमेरिकन मेडिकल डिवाइस ट्रेड एसोसिएशन) के अध्यक्ष स्कॉट वाल्कर से मुलाकात की थी। एडवामेड ने वाशिंगटन में कई बार गोलबंदी की है, जिससे भारत अहम मेडिकल उपकरणों के दाम तय करने के फैसले को खत्म करे। इस लॉबी को ट्रंप के राजनीतिक खेमे का नजदीकी माना जाता है। भारत का मेडिकल उपकरण आयात लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके दाम में धीरे धीरे गिरावट आई है। इसकी वजह से ऑपरेशन पहुंच के भीतर हुए हैं। आयात के तमाम स्रोतों के बावजूद अमेरिका में बने मेडिकल उपकरण की भारत के बाजार में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, जो 2016-17 में उच्चतम स्तर पर था। लेकिन उसके बाद से अमेरिका से आयात कम हुआ है। भारत में 2018-19 में होने वाले 1.7 अरब डॉलर केमेडिकल उपकरणों के आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 19.8 प्रतिशत है, जो एक साल पहले के 23.7 प्रतिशत की तुलना में कम है।

कारोबारी सौदे की योजना

एक वरिष्ठ कारोबारी वार्ताकार के मुताबिक भारत ने आपस में स्वीकार्य समग्र कारोबारी पैकेज की योजना तैयार की थी, जिसमें दोनों पक्षों के लिए एक स्वीकार्य समाधान दिया गया था। दोनों देशों के बीच यह पूर्ण रूप से कारोबारी समझौते का पहला कदम होगा। पिछले साल प्रस्तावित क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी को छोड़ने के बाद यह भारत की प्राथमिकता में है। वार्ताकार ने कहा कि अभी भी मुक्त व्यापार समझौता बहुत दूर की बात है।

अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत 29 प्रमुख आयातों (खासकर कृषि आयात) पर लगाया गया भारी शुल्क खत्म करे, जो अमेरिका से होता है। भारत ने महंगे सेब, बादाम, अखरोट और वाइन पर 50 प्रतिशत तक कर लगा रखा है।

अनुमान है कि नए करों से 24 करोड़ डॉलर अतिरिक्त कर आएगा और भारत का दावा है कि अमेरिका द्वारा स्टील पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और एल्युमीनियम उत्पादों पर लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क से होने वाले घाटे की भरपाई हो सकेगी। अमेरिका ने यह शुल्क भारत सहित तमाम देशों पर मई 2018 में लगाया था।

द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका की प्रमुख मांगों में रहा है और भारत भी इसे दोहराता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ट्रंप ने उनसे बहुत जल्द कारोबारी समझौता होने का वादा किया है।

इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपना आक्रामक रुख छोड़ा है। अमेरिका ने भारत को सीधा निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उसने भारत पर चीनी उत्पादों के आयात की तर्ज पर कर बढ़ाने की बात कहना बंद कर दिया है।

अगले सप्ताह होगी कारोबारी बातचीत

- बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयातित मेडिकल उपकरणों पर 5 प्रतिशत स्वास्थ्य उपकर लगाने की घोषणा की थी
- भारत कर हटाने को तैयार नहीं, कारोबारी छूट पर हो रहा है विचार
- अगले सप्ताह अमेरिका के वाणिज्य मंत्री रॉबर्ट लाइटहाइजर के भारत आने का कार्यक्रम

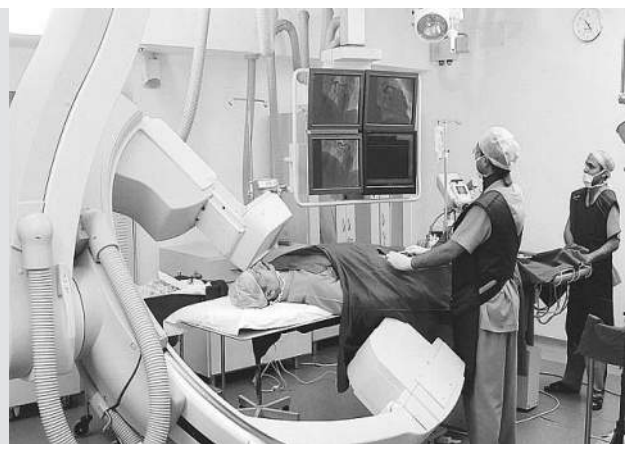

बीएस सूडोकू 3659 | परिणाम संख्या 3658

	8				5	7		2
				6			8	
				4	2		3	
		3		7				5
4	7						6	3
2				1		4		
	1		9	3				
	3			8				
9		8	6				1	

9	1	5	4	8	7	6	3	2
2	3	4	6	5	9	1	7	8
6	7	8	3	1	2	9	4	5
5	6	2	9	7	4	8	1	3
1	4	9	8	3	5	7	2	6
3	8	7	2	6	1	4	5	9
7	9	3	1	2	8	5	6	4
4	5	6	7	9	3	2	8	1
8	2	1	5	4	6	3	9	7

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

दिल्ली

सराफा : रुपये की विनिमय दर में गिरावट के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव शुक्रवार को 112 रुपये बढ़कर 1,249 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमत भी 94 रुपये बढ़कर 47,305 रुपये किलो पहुंच गई। सोना गुरुवार को 41,137 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 47,211 रुपये किलो पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमत क्रमशः 1,566.7 डॉलर प्रति औंस और 17.79 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।

कानपुर

गेहूं लूज 2010/2020, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550, सरसों खल 2000/2050, पामोलिन 1550/1600, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1475/1500, अलसी 6500/6600,

लखनऊ

गेहूं दड़ा 2010/2015, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4250, लालमती 3150/3200, चावल (सोना) 2700/2750,

चंदौसी

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1363, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1436, फ्लेक 1383, डीएमओ 987, टरपीन लैस बोल्ड 1460

मुजफ्फरनगर

गुड़ (40 किलो): लड्डू 1050/1150, खुरपा 1000/1020,चाकू 1050/1100, रसकट 880/900, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3300, सिहोरा ×, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3250, चीनी हाजिर 3500/3600

हापुड़

गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/980, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4250, खलः सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2350, चना छिलका 2100/2150, चोकर मोटा (34 किलो) 730/740

श्रीगंगानगर

गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3750/3800, जौ 2100/2125, सरसों लूज 3900/3950

जोधपुर

गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 7000/7100, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1800/1825, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6900/7000, मोठ 5900/6000, रायडा 3700/3800, मूंगफली 4300/4500, सींगदाना 6000/6500, जीरा 15000/16500, मगज तरबूज 12800/13000, तरबूज बीज ×

जयपुर

अनाजः चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3775/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2800/2900, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4320/4325, सरसों एक्सपेलर निवाई 8200, कोल्हू कच्ची घानी टोंक 8400, राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यूअस 1400, डीओसी (टन): सरसों जयपुर 16500, कोटा 15500,अलवर 15000, निवाई 15500

खन्ना

जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)112, राइसब्रान (अखाद्य) 109, खल सरसों 1900, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1100, लाल 1100, कंटीन्यूअस 1225, सरसों (टन) 16000, अनाजः गेहूं 2075/2080, आटा (50 किलो)1150, मैदा 1250, चोकर (49 किग्रा) 1020, चोकर (30 किग्रा) 620, मक्की बिहार 2100/2110

बठिंडा

रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4060/4100, हरियाणा 4040/4060, राजस्थान 4000/4060, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2000/2010, गेहूं चोकर (28 किलो) 580

फाजिल्का

गेहूं 2040/2050, सरसों 4050/4150 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 4300/4400, कपास नरमा (क्विं.) 5050/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400, जे-34 (चिलकी) 3350/3400

जालंधर

गेहूं दड़ा 2020/2040, चावल परमल कच्चा 2325/2365, *भाषा/एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 304

अनदेखी न करें

अधिकांश नहीं तो भी कई आर्थिक टीकाकारों का यही कहना है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर नहीं किया। इस बात पर लगभग सहमति है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए और निकट भविष्य में भी संभावनाएं कुछ अच्छी नहीं नजर आ रहीं। इससे इनकार नहीं कि सरकार ने कई प्रमुख आर्थिक पहलों में गोलमाल किया, संरक्षणवाद को अपनाया और रोजगार तथा व्यापार के मोर्चे पर भी उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। सबसे अहम बात यह कि यदि कोई मान लेता है कि इस वर्ष वृद्धि दर 5 फीसदी है और अगले वर्ष 6 फीसदी रहेगी तो सन 2020-21 तक की तीन वर्ष की अवधि में वृद्धि औसतन 5.7 फीसदी रहेगी। यह आंकड़ा मनमोहन सिंह सरकार के अंतिम वर्ष के 6.2 फीसदी के स्तर से काफी कम है और नई सदी के आरंभिक सालों से यह स्तर देखने को नहीं मिला था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अस्पष्ट बजट भाषण से आपको इसका अंदाजा नहीं मिलेगा। उनका लिखित भाषण कई पूर्ववर्तियों के भाषण से छोटा था लेकिन बात पर जोर देने के लिए उसे दोहराने की आदत के चलते लंबा हो गया। वह मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल के दो चरणों का जिक्र करके मंदी को स्पष्टवादिता से स्वीकार कर सकती थीं। पहले चार वर्ष में औसत वृद्धि दर 7.7 फीसदी थी और दोनों अवधि को जोड़ दिया जाए तो यह औसतन 6.9 फीसदी है।

यह उतार-चढ़ाव बीती चौथाई सदी या उससे अधिक समय से बना हुआ है। सिंह सरकार के कार्यकाल के अंतिम तीन वर्ष में कमजोर वृद्धि दर के पहले तीन वर्ष तक 7.5 फीसदी की बढ़िया औसत वृद्धि हासिल हुई। इसने उस दौर के वैश्विक वित्तीय संकट को भी धता बता दिया। इसी तरह 2000 से 2003 के बीच की 4.2 फीसदी की कमजोर औसत दर के पहले 6.3 फीसदी की ऊंची वृद्धि दर देखने को मिली थी। इसके बाद भी वृद्धि में तेजी आई। संक्षेप में वृद्धि धीमी, तेज और दोबारा धीमी हो सकती है और ऐसा कहने में शर्माने की कोई बात नहीं।

धीमी वृद्धि के मौजूदा दौर में अस्वाभाविक बात यह है कि यह बिना बाह्य कारणों (कच्चे तेल की ऊंची कीमत और/अथवा मॉनसून की लगातार विफलता) के आई है। जबकि बीते 50 वर्ष के दौरान हर बार धीमेपन के पीछे ऐसी कोई न कोई वजह थी। मंदी का मौजूदा दौर कहीं अधिक गंभीर है। यदि सबकुछ ठीक होने पर भी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कमजोर है तो मतलब यह कि राज्य सत्ता के साथ ही गड़बड़ी है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

यह बात ध्यान देने लायक है कि मोदी ने कौन से सामाजिक आर्थिक बदलाव गढ़े हैं: वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में नाटकीय सुधार हुआ है, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था, शौचालय, बिजली, डिजिटल लेनदेन और अब नि:शुल्क चिकित्सा बीमा, किसानों को नकद हस्तांतरण आदि। इसके अतिरिक्त जैसा कि सीतारमण ने कहा कि मूल मुद्रास्फीति समेत वृहद आर्थिक संतुलन सहज है। राजकोषीय चुनौती पर जरूर वह बातें स्पष्ट नहीं कर पाईं और उससे जुड़े प्रश्न अनुत्तरित रह गए। इसके बावजूद परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, यह बात डिजिटल ढांचे के बारे में भी कही जा सकती है। डेटा खपत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ी है। अगले कुछ वर्षों में उपरोक्त तमाम आंकड़ों में और सुधार आएगा। इस प्रकार तमाम लोगों का जीवन बदल रहा है।

मोदी के आलोचक अक्सर इन बदलावों और इनके महत्त्व को स्वीकार करने में चूक जाते हैं। हो सकता है सरकार की नाकामियां अधिक स्पष्ट और मानीखेज हैं: रोजगार के मोर्चे पर खराब होती स्थिति, खपत कमजोर होना, निवेश पर नकारात्मक असर, निर्यात में ठहराव, कई अहम नीतिगत सुधारों को लेकर विधायी निष्क्रियता, किसानों के समक्ष तमाम चुनौतियां आदि इसके उदाहरण हैं। भय और संस्थागत क्षति को इसमें जोड़ा जा सकता है।

मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों को तमाम मसलों पर अपनी आलोचना को सहजता से लेना होगा और रोजगार की समस्या को हल करना होगा। क्योंकि बढ़ती असमानता और वृद्धि के लाभ के असमान से निपटने में यह अहम है। सीतारमण ने अपने भाषण में इनमें से कुछ को हल करने का प्रयास किया लेकिन 160 मिनट के बाद भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाईं। अभी कई मोर्चों पर काफी कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग तरीके अपनाने होंगे। यदि ये प्रयास बढ़े और वृद्धि में सुधार हुआ तो मोदी सरकार का आर्थिक रिकॉर्ड अभी भी चमक सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी वृद्धि का अगला दौर आता ही होगा।

अजय मोहंती

वृहद नीति से हासिल हो सकते हैं कुछ हल

देश को दीर्घावधि के ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। इसमें एकीकृत जीएसटी और प्रत्यक्ष कर दरें शामिल हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **अजय शाह**

देश कारोबारी मंदी के चक्र से गुजर रहा है और वृद्धि दर में भी गिरावट का रुख है। वृहद आर्थिक नीति के उपाय कारोबारी चक्र की समस्या को हल कर सकते हैं लेकिन समग्र समस्या को हल करने की उनकी क्षमता सीमित है। हमें राजकोषीय विस्तार को लेकर सचेत रहना होगा क्योंकि वित्तीय कमजोरी की स्थिति बनी हुई है। उपयोगी राह यही होगी कि कर नीति और कर प्रशासन में जरूरी ढांचागत सुधारों को अंजाम दिया जाए। ये लंबे समय से लंबित हैं।

सन 1991 से 2011 तक देश में तेज वृद्धि का दौर रहा। उसके बाद इसमें गिरावट आई। लंबी अवधि के रुझान के शीर्ष पर कारोबारी चक्र की अवधारणा, मुनाफे में कमी, इन्वेंटरी और दीर्घावधि के रुझान के इर्दगिर्द का निवेश आते हैं। फिलहाल हम कारोबारी चक्र में मंदी का भी सामना कर रहे हैं।

पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि वृहद नीति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के उपायों का इस्तेमाल बचाव के लिए किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति पहले ही मुद्रास्फीति को लक्षित करके ऐसा कर रही है। 91 दिन के ट्रेजरी बिल की दर जो मौद्रिक नीति के रुख के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है वह 2013 में 11 फीसदी के वास्तविक स्तर पर थी। उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विनिमय दर को लक्ष्य बनाकर चल रहा था। अब जबकि आरबीआई मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाकर चल रहा है तो यह 5 फीसदी के स्तर पर है। यानी यह वास्तविक नीतिगत दर में 6 फीसदी की कमी है। यदि मौद्रिक नीति समिति सावधानीपूर्वक काम करती है और ऐसी ब्याज दर तलाशती है जो खुदरा महंगाई का 4 फीसदी का लक्ष्य हासिल कर सके, मौद्रिक नीति सही है।

राजकोषीय नीति की बात करें तो क्या हम कर दरों में भारी कटौती करके क्रय शक्ति में सुधार कर सकते हैं? या व्यय में इजाफा करके यही प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है? इस राह पर चलने से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि 2007-08 के उच्चतम स्तर से उठान पर रहे निजी कॉर्पोरेट निवेश में अब भारी गिरावट आ चुकी है। देश में राजकोषीय नीति अपना रुख सकल घरेलू उत्पाद के एक या दो फीसदी तक बदल सकती है लेकिन दिक्कत इससे कम से कम पांच गुना बड़ी है।

सरकार का ऋण लेने का तरीका गलत है। अधिकांश उधारी अनुषंगी ऋणदाताओं से वित्तीय दबाव के माध्यम से ली जाती है। जब अनिवार्यता समाप्त हो जाती है तो वित्तीय नियामकों से कहा जा सकता है कि वे जबरिया निवेश को सरकारी बॉन्ड में डालें। इसके लिए सांविधिक तरलता अनुपात बढ़ाया जा सकता है। यह आर्थिक सुधारों के क्रम को उलटने के समान होगा और औपचारिक वित्तीय मध्यस्थता पर प्रभावी कराधान बढ़ेगा। जब अर्थव्यवस्था में कर दरों के ऊपर नीचे होने की आशंका बढ़ती है तो अनिश्चितता पैदा होती है। व्यक्तिगत स्तर पर लोग कर नीति में लंबी स्थिरता चाहते हैं ताकि वे निवेश को लेकर आश्वस्त रहें।

आदर्श स्थिति में हमें तेजी के वर्षों यानी 2007-08 में 4 फीसदी का प्राथमिक अधिशेष मिलता जो 2020-21 में 4 फीसदी के घाटे को सहन करने की गुंजाइश तैयार करता। परंतु खेद की बात है कि देश की राजकोषीय नीति अच्छे दिनों में भी भारी भरकम अधिशेष नहीं तैयार कर पाती। यही कारण है कि मंदी के पहले हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और सरकारी उधारी की औसत लागत एक दूसरे के अधिक करीब हैं। ऐसे में संभव है कि ऋण/जीडीपी अनुपात में इजाफा देखने को मिले।

वृहद नीति में भी किसी का नुकसान न करने की भावना प्रबल होती है। देश के नीति निर्माता सन 2001 में राजकोषीय तनाव और 2010 में मुद्रास्फीति के कारण अत्यंत खतरनाक स्थिति में थे। इन अनुभवों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। हमें सन 2022 तक कोई राजकोषीय संकट या मुद्रास्फीतिक संकट नहीं चाहिए।

राजकोषीय नीति इस स्थिति से कैसे निकलेगी? इसकी पूर्व शर्त यह है कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी और बॉन्ड बाजार में सुधार को अपनाया जाए ताकि सरकार और ऋणदाताओं के बीच बेहतर रिश्ते कायम हो सकें। इसके अतिरिक्त व्यापक तौर पर स्वैच्छिक ऋणदाताओं से कर्ज लेने की क्षमता पैदा होगी। इसके लिए सन 2015 में शुरू किए गए कार्यक्रम को दोबारा अपनाना होगा।

हमें इस अवसर का लाभ कर नीति में लंबे समय से लंबित ढांचागत बदलावों को बढ़ावा देने में लेना चाहिए। हमें एक स्पष्ट और सहज प्रत्यक्ष कर संहिता की आवश्यकता है जिसमें सभी निगमों और व्यक्तियों के लिए 20 फीसदी की सपाट कर दर हो। हमें एकीकृत आधार की आवश्यकता है। यानी वस्तु एवं सेवा कर में भी 8 से 10 फीसदी की एकल दर। इसके अलावा हमें नए कर प्रशासन कानून की आवश्यकता है जो कर प्रशासन में नियम कायदे लागू करे।

जो सुधार काफी लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें स्थायी ढांचागत सुधार के रूप में पेश किया जाना चाहिए, न कि मौजूदा संकट से निपटने के फौरी उपाय के तौर पर। इससे वांछित आशावाद उत्पन्न होगा और निजी क्षेत्र के लिए आदर भाव उपजेगा। यदि ऐसे बदलाव आर्थिक तनाव से निपटने की अल्पकालिक प्रतिक्रिया के रूप में पेश किए गए तो निजी क्षेत्र इन्हें अस्थिर मानेगा और अर्थव्यवस्था को इससे पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

वृहद नीति आर्थिक मंदी से कैसे निपट सकती है इस बारे में सहज बातचीत की अपनी भूमिका है। बहरहाल हमें वृहद नीति की भूमिका को बहुत बढ़ाचढ़ाकर भी पेश नहीं करना चाहिए। भारत में मौद्रिक नीति की भूमिका सीमित है क्योंकि उन वित्तीय सुधारों को अंजाम नहीं दिया गया जो मौद्रिक नीति पारेषण को प्रभावी बना सकते थे। हमारे देश में राजकोषीय नीति इसलिए सीमित है क्योंकि घाटे की समस्या बनी रहती है और उधारी की प्रक्रियाएं खामियों से भरी हुई हैं। भारतीय व्यवस्था में मौद्रिक नीति का मानक प्रभाव है कम क्षमता। चाहे जो भी हो वह केवल कारोबारी चक्र के उतार-चढ़ाव का ही समाधान कर सकती है। वह वृद्धि को प्रभावित नहीं कर सकती।

सन 2011 के बार से वृद्धि के रुझान में लगातार गिरावट के वास्तविक कारणों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि इसकी वजह निजी निवेश में आई गिरावट है। इस समस्या का हल करने के लिए निजी क्षेत्र की असहजता को समझते हुए उसे हल करना होगा। इसमें कई समस्याएं शामिल हैं, कानून की समस्या, आपराधिक न्याय प्रक्रिया की समस्या, कर प्रशासन और आर्थिक नियमन की समस्या आदि। ऐसा करते हुए हम आर्थिक स्वायत्तता की कहीं अधिक बड़ी समस्या तक भी पहुंचेंगे और राज्य सत्ता की सक्रियता को कम करने की आवश्यकता तक भी।

`आप' के लिए सत्ता के साथ आंतरिक लोकतंत्र भी जरूरी

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

इस बात को लेकर शायद ही कोई संदेह है कि 11 फरवरी को आने वाले चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी (आप) ही दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आप सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों ने दिल्ली के निवासियों खासकर निचले तबके का ध्यान खींचा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सीटें इस बार दोगुनी या फिर तिगुनी भी हो सकती हैं लेकिन वह संख्या भी छह या नौ तक ही पहुंचेगी। कांग्रेस तो इस चुनाव में कोई असर डालने की स्थिति में दिख ही नहीं रही है। लेकिन आप पार्टी मजबूती से लड़ रही है और यही बात हालात को पेचीदा बना रही है।

करीब 30 वर्षों से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय कमल मित्र चिनॉय 40 वर्षों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) का सदस्य रहने के बाद वर्ष 2014 में आप से जुड़ गए थे। उन्होंने उस समय भाकपा से इस्तीफा देने की वजह बताते हुए कहा था, 'यह समय भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए बेहद अहम है। यह कहना आसान है कि आप के पास कोई सिद्धांत नहीं है। ग्राम्शी ने बार-बार इस पर जोर दिया था कि सभी लोग किसी न किसी तरह से बुद्धिजीवी होते हैं। चिनॉय ने अपने एक लेख में कहा था, 'बड़ा फर्क परंपरागत विचारधाराओं का बचाव एवं वैधता देने वाले परंपरागत बुद्धिजीवियों और ताकत के एकाधिकारवादी इस्तेमाल के बीच होता है। वहीं बदलाव और क्रांति के लिए जरूरी माने जाने वाले संगठित बुद्धिजीवी जैसे उनके प्रतिद्वंद्वियों की जड़ें लोकप्रिय आंदोलनों और लोकप्रिय संस्कृति में होती हैं।'

लेकिन इसके दो साल बाद ही चिनॉय ने आप से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने केजरीवाल को लिखे एक व्यक्तिगत पत्र में कहा था कि उन्हें अपनी राह में बदलाव करने की जरूरत है और अपने इर्दगिर्द मौजूद लोगों के गिरोह से आजाद होना होगा। साफ था कि सत्ता का एकाधिकारवादी इस्तेमाल फिर से अपना सिर उठा रहा था।

बेहद अजीब बात है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक से आलोचक बनने वाले सभी लोग आज उसी बात को थोड़े अपरिष्कृत रूप से कह रहे हैं कि केजरीवाल अपने आसपास मौजूद कुछ लोगों के हाथों में खिलौना बनकर रह गए हैं। इससे एक पेचीदा समस्या खड़ी हो रही है। क्या भारत के सभी दूसरे दलों से अलग होने की मंशा रखने वाले एक लोकतांत्रिक दल के लिए अ-लोकतंत्र ही आधार बन सकता है?

आप ने अपने संक्षिप्त जीवनकाल में खुद को शासन के कई क्षेत्रों में स्थापित कर लिया है। लेकिन पार्टी के भीतर लोकतंत्र के मामले में वह पीछे है। पंजाब में चुनाव, दिल्ली में नगर निगमों के चुनाव हारने के बाद उठे बगावती सुर और प्रशांत भूषण एवं योगेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, उसने पार्टी के भीतर लोकतंत्र के अभाव को उजागर कर दिया। भूषण, यादव और आनंद कुमार पर आरोप लगा था कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को धूमिल करने का काम किया था। इस आरोप को सभी नेताओं ने सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि वे केवल पार्टी को अधिक लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे।

पंजाब में आजाद-खयाल रखने वाले विधायक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने 2014 के आम चुनाव के ऐन पहले शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आप का दामन थाम लिया था। आप नेताओं का कहना था कि गुरदासपुर में सुच्चा सिंह के भाषण से केजरीवाल काफी प्रभावित हुए थे। आप को पंजाब विधानसभा के दो उपचुनावों में शिकस्त मिली तो केजरीवाल ने राज्य में पार्टी गतिविधियां चलाने का जिम्मा सुच्चा सिंह को ही सौंप दिया। वैसे सुच्चा सिंह कांग्रेस में भी अमरिंदर सिंह के साथ काम कर चुके हैं। वर्ष 2009 में अमरिंदर उन्हें कांग्रेस के पाले में ले गए थे। उस समय अमरिंदर प्रताप सिंह बाजवा के लिए प्रचार कर रहे थे और बाजवा को जीत दिलाने में सुच्चा सिंह की भी भूमिका स्वीकार की जाती है।

लेकिन सुच्चा सिंह कोई मेहरबान शख्स नहीं हैं। आप कहती है कि सुच्चा सिंह एक वीडियो में नोटों का बंडल लेते हुए नजर आ चुके हैं। लेकिन उनके विरोधी तक यह कहते हैं कि सुच्चा सिंह कई मामलों में गलत हो सकते हैं लेकिन वह भ्रष्ट नहीं हैं। वह कहते हैं कि उन्हें उस समय फंसाया गया जब उन्होंने केजरीवाल और उनके 'गिरोह' का यस मैन बनने से इनकार कर दिया।

कभी आप के अंदरूनी तंत्र का हिस्सा रहे और चार दशकों से मनीष सिसोदिया के मित्र रहे कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी है और अब वह आप के सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं।

समाज-विज्ञानी आनंद तेलतुंबडे कहते हैं कि आप का दिल्ली की सत्ता में वापस लौटना इस बात पर निर्भर करता है कि वह एक 'स्टार्टअप' के तौर पर खुद को फिर से तलाश पाती है या नहीं। इसके लिए उसे खुद को नए सिरे से खड़ा करने के साथ ही अपने 'ग्राहकों' यानी दिल्ली की जनता से माफी भी मांगनी होगी। उनका कहना है कि आप का कारोबारी मॉडल मेट्रो शहरों की नव-उदारवादी पीढ़ी को आकर्षित करता है। यह तबका आदर्शवादी है और भ्रष्ट एवं अक्षम नेताओं के हाथों भारत की क्षमताएं धूसरित होते हुए देखकर व्यथित है।

आप की पूर्व विधायक अलका लांबा कहती हैं कि वर्ष 2017 में हुए नगर निगम चुनावों तक सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन उस चुनाव में टिकट वितरण को लेकर किसी भी विधायक से सलाह-मशविरा नहीं किया गया और फिर हालात बिगड़ने शुरू हो गए। इस दौरान आशुतोष और आशिष खेतान जैसे कई अहम नेताओं ने भी अंदरूनी लोकतंत्र की कमी का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी। आप में मतभेद को लेकर आखिरी शब्द अभी कहे नहीं गए हैं। क्या आप अलोकतांत्रिक पार्टी संरचना के दम पर वास्तव में लोकतांत्रिक नतीजे दे सकते हैं? आम आदमी पार्टी को इस विरोधाभास का जवाब तलाशना होगा।

कानाफूसी

महंगी होगी सूचना

मध्य प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना जल्दी ही महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में सूचना का आवेदन करने के शुल्क में 10 गुना बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रही है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो लोगों को सूचना हासिल करने के लिए मौजूदा 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का भुगतान करना होगा। सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि मध्य प्रदेश को उन राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके जहां यह शुल्क पहले से अधिक है। बहरहाल, प्रदेश के सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार यह कदम जानबूझकर उठा रही है ताकि सूचना पाने के लिए बढ़ते आवेदनों पर रोक लगाई जा सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके।

अखिलेश का निशाना

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की चुटकी लेने का कोई अवसर जाने नहीं देते हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर था तब उन्होंने भाजपा नेताओं के भड़काऊ और अनुचित वक्तव्यों को निशाने पर लिया। यादव ने कहा कि भाजपा के नेता ऐसे वक्तव्य हताशा में दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पार्टी का जनाधार खिसक रहा है। वैसे तो दिल्ली चुनावों में समाजवादी पार्टी का कुछ भी दांव पर नहीं लगा है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भाजपा को होने वाला कोई भी नुकसान पार्टी का मनोबल बढ़ाएगा क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बड़ी तादाद में निवास करते हैं। हाल के वर्षों में खुद उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रभाव काफी कम हुआ है।

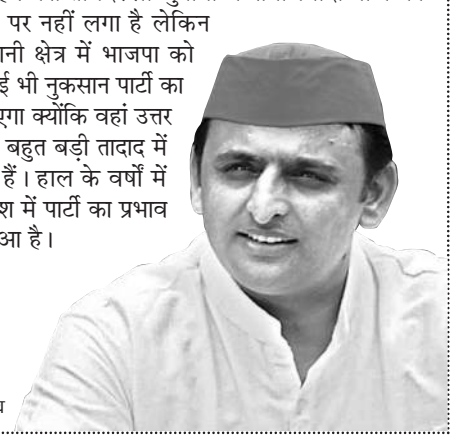

अखिलेश यादव

आपका पक्ष

विश्व की दूसरी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

चीन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों से धीमी वृद्धि दर, घटता निवेश, मांग में कमी, अनियंत्रित महंगाई दर, घटती कृषि उपज आदि कारणों से देश की अर्थव्यवस्था संकट में घिरी है। हाल में जारी आर्थिक समीक्षा में देश की खस्ता अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार धीमी पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बताया गया है जो किमात्र 2.9 प्रतिशत है। वैश्विक वृद्धि दर धीमी पड़ने की प्रमुख वजह अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध तथा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी है जिस वजह से वैश्विक हलचल का

परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से पड़ता है। हालांकि आर्थिक सुस्ती का कारण वैश्विक के अलावा आंतरिक भी है। इसे समय रहते सुधारा नहीं गया जिस वजह से भारत आर्थिक मोर्चे पर परेशानी झेल रहा है। पिछले छह

आम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 103 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई

महीनों में भारत का चालू खाता घाटा 1.5 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2018-2019 में 2.1 प्रतिशत था। हाल में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर से दिसंबर 2019 में देश में बेरोजगारी दर 7.5 प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा रोजगार सृजन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बुनियादी ढांचे पर 103 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए जिससे बेरोजगारी संकट कम हो सके।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

सावधानी ही एकमात्र बचाव का उपाय है

कोरोनावायरस से पीड़ित व्यक्ति में छींक आने के साथ खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस फूलने और थकान जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसके संक्रमण से बचाव के लिए साफ-सफाई के साथ ही संक्रमित लोगों से दूर रहने जरूरत है। इसके अलावा कई दूसरी सावधानियां जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने पर मास्क का इस्तेमाल करना, बुखार-खांसी होने पर घरेलू उपाय के बजाय चिकित्सक से सलाह लेना आदि का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इस कोरोनावायरस के इलाज के लिए अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इससे दूरी बनाए रखना ही अहम बचाव है। फिर भी अगर हमें संदेह हो तो चिकित्सक से मिलें और आसपास रहने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही, बीमार या संदेहास्पद व्यक्ति अगर स्वयं मास्क का उपयोग करे तो बेहतर होगा।

स्नेहा तिवारी, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

इस्पात के दाम बढ़ते रहने पर संशय

मांग वृद्धि के संकेत नहीं मगर नवंबर से लगातार बढ़ रहे दाम

अदिति दिवेकर
मुंबई, 7 फरवरी

मांग में सुधार के संकेत न होने के बावजूद घरेलू इस्पात उद्योग नवंबर से लगातार अपने उत्पादों के दाम बढ़ाता आ रहा है। इस्पात विकास एवं संवृद्धि संस्थान (आईएनएसडीएजी) के महानिदेशक सुषिम बनर्जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि मांग वृद्धि के ऐसे जरा भी संकेत नहीं है जिससे दामों में यह इजाफा कायम रखा जा सके। बुनियादी संरचना की मांग में अभी इजाफा नहीं हुआ है और वाहन क्षेत्र कमजोर चल रहा है।

घरेलू इस्पात उत्पादक फरवरी के लिए उत्पादों के दामों में करीब 2,000 रुपये प्रति टन तक का इजाफा कर चुके हैं। बनर्जी ने कहा कि फरवरी की दाम वृद्धि भी स्टॉकिस्टों के पास रखे स्टॉक की मांग बढ़ने की उम्मीद से हुई है। अब तक कोई मजबूत मांग नहीं है। कच्चे माल के अधिक दाम, वैश्विक स्तर पर इस्पात के दामों में इजाफा और मांग बढ़ने की उम्मीद के कारण ही नवंबर के बाद से घरेलू इस्पात उत्पादकों ने हर महीने दाम बढ़ाए हैं। फिलहाल घरेलू बाजार में हॉट-रॉल्ड इस्पात के दाम प्रति टन 40,000 रुपये के स्तर पर चल रहे हैं जो वर्ष 2019 के मध्य में दर्ज किए गए 15 महीने के निचले स्तर प्रति टन 33,500 रुपये से अधिक हैं। हालांकि दामों का मौजूदा स्तर अक्टूबर 2018 में हॉट रॉल्ड के दर्ज किए गए 47,000 रुपये प्रति टन की तुलना में कम हैं।

टाटा स्टील, सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील, नवीन जिंदल की अगुआई वाली जिंदल स्टील ऐंड पावर और सरकारी स्वामित्व वाला भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) देश के शीर्ष इस्पात उत्पादकों में शामिल हैं। मुंबई स्थित एक कारोबारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि दामों में इजाफा करना ठीक है, सवाल दामों में इस इजाफे के कायम रहने का है। मांग है ही कहां?

उद्योग के कुछ अधिकारियों की राय है कि वित्त वर्ष 21 के आम बजट में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाए गए सीमा शुल्क से इस्पात बाजार में मामूली-सी मांग आ सकती है। बनर्जी ने कहा कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की हल्की-सी मांग घरेलू इस्पात उद्योग की मांग में जान फूंकने के लिए पर्याप्त नहीं है।

घरेलू इस्पात उद्योग की कुल मांग में सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र और वाहन उद्योग का रहता है। कुल इस्पात खपत का करीब 10 से 12 प्रतिशत का मामूली हिस्सा ही टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का रहता है।

एडलवाइस सिक्योरिटीज के एक नोट में कहा गया है कि हमारे विचार से यह अपेक्षित मूल्य वृद्धि (फरवरी में) शायद पूरी तरह से कारगर न रहे क्योंकि जापान के फ्री ऑन बोर्ड दाम सीएफआर वियतनाम के दामों में गिरावट का अनुसरण कर सकते हैं। इसके अलावा जब चीन की कंपनियां 9 फरवरी को फिर से काम शुरू करेंगी तो चीन के दामों में गिरावट आ सकती है। इससे घरेलू कीमतों की तुलना में आयातित कीमतों में गिरावट आने के आसार हैं। संयुक्त संयंत्र समिति के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से मई के दौरान भारत का घरेलू इस्पात उपभोग 6.65 करोड़ टन रहा है जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3.65 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि उत्पादन पिछले साल की तुलना में दो प्रतिशत अधिक 6.766 करोड़ टन रहा है।

उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि यह बात परखने के लिए कि क्या दाम वृद्धि बनी रहेगी, घरेलू इस्पात उद्योग के लिए अगले दो से तीन महीने बहुत महत्त्वपूर्ण होंगे क्योंकि अधिक उपभोग की अवधि मई तक जारी रहेगी। मुंबई के कारोबारी और बंबई आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि मांग बेहद कमजोर है और उत्पादक पूरी तरह से अवसरवादी बन रहे हैं।

इस्पात के लिए जुलाई से सितंबर तक की अवधि को आमतौर पर सुस्त मांग वाले मौसम के रूप में माना जाता है क्योंकि मॉनसून की वजह से देश भर में औद्योगिक गतिविधियों में ठहराव आ जाता है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आवास के लिए उपभोक्ता ऋण को बढ़ावा देने के लिए राहत के कुछ उपायों की घोषणा किए जाने के बाद कारोबारियों को रियल एस्टेट क्षेत्र से मांग में इजाफा होने की उम्मीद है। बनर्जी ने बताया कि अब तक उद्योग में केवल यही एकमात्र सकारात्मक बात देखी जा सकती है कि उपभोग के लिहाज से अनिश्चितता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनियों को मांग में मंदी की वजह से पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ी है। उद्योग इस स्थिति से निकल चुका है। अब तक केवल यही एकमात्र वास्तविक सकारात्मक बात है।

इस्पात उद्योग

- घरेलू इस्पात उत्पादक फरवरी के लिए उत्पादों के दामों में करीब 2,000 रुपये प्रति टन इजाफा कर चुके हैं
- घरेलू बाजार में हॉट-रॉल्ड इस्पात के दाम प्रति टन 40,000 रुपये के स्तर पर चल रहे हैं जो वर्ष 2019 के प्रति टन 33,500 रुपये से अधिक हैं
- दामों का मौजूदा स्तर अक्टूबर 2018 में हॉट रॉल्ड के दर्ज किए गए 47,000 रुपये प्रति टन की तुलना में कम हैं
- घरेलू इस्पात उद्योग की कुल मांग में सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र और वाहन उद्योग का रहता है
- कुल इस्पात खपत का करीब 10 से 12 प्रतिशत का मामूली हिस्सा ही टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का रहता है
- अप्रैल-मई के दौरान घरेलू इस्पात उपभोग 6.65 करोड़ टन रहा जो पिछले साल से 3.65 फीसदी ज्यादा है
- उत्पादन पिछले साल की तुलना में दो प्रतिशत अधिक 6.766 करोड़ टन रहा

इस्पात के दामों में वृद्धि

महीना	इजाफा
नवंबर 2019	500-750
दिसंबर 2019	1,000-1,500
जनवरी 2020	1,000 तक
फरवरी 2020	1,700-2,000

(इजाफा प्रति टन रुपये में)

स्रोत : इस्पात उद्योग के कारोबारी

एसएमपी कीमत बढ़ोतरी पर निजी और सहकारी डेयरी में टकराव

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 7 फरवरी

स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण निजी और सहकारी डेयरियों के बीच टकराव पैदा हो गया है। वैवाहिक सीजन की मांग में अचानक बढ़ोतरी और पिछले साल प्रतिकूल मौसम के चलते एसएमपी के उत्पादन में गिरावट के कारण इसकी किल्लत पैदा हुई है।

निजी डेयरियों ने आइसक्रीम विनिर्माताओं और कन्फेक्शनरों (बिस्कुट एवं चॉकलेट विनिर्माता) समेत थोक ग्राहकों की इस मांग का समर्थन किया है कि शून्य शुल्क पर 50,000 टन एसएमपी के आयात को मंजूरी दी जाए। लेकिन सहकारी डेयरियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसका किसानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

दरअसल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार के समक्ष एसएमपी के आयात को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। इस समय एसएमपी के दाम 310 से 320 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। इनमें पिछले एक महीने के दौरान 15 फीसदी बढ़ोतरी हुई है और ये एक साल पहले की तुलना में दोगुने हो गए हैं।

कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ (केएमएफ) के प्रबंध निदेशक बी सी सतीश ने कहा, 'एसएमपी के दाम अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर के आसपास बने हुए हैं, इसलिए इसकी कीमतों में आगे और बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। मौजूदा स्तरों से दाम और बढ़ने पर ग्राहक तरल दूध और अन्य विकल्पों का उपयोग शुरू करेंगे। इस तरह हाल की कीमत बढ़ोतरी अस्थायी है। एसएमपी की कीमतों में गिरावट शुरू होगी और ये अगले एक महीने में स्थिर हो जाएंगी।' केएमएफ भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेयरी संघ है, जो रोजाना 86 लाख लीटर तरल दूध का प्रबंधन करता है और नंदिनी ब्रांड के डेयरी उत्पादों की बिक्री करता है।

सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले महीने की शुरुआत में उद्योग से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई थी ताकि कीमतों में बढ़ोतरी की वजहों का पता लगाया जा सके और नीतिगत दखल की रणनीति बनाई जा सके। देश की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक आर एस सोढी ने कहा, 'हम दुग्ध उत्पादकों की आमदनी घटाने के सीआईआई के किसान विरोधी कदम का विरोध कर रहे हैं, जिसने शून्य शुल्क पर सस्ते एसएमपी आयात की सिफारिश की है। निजी डेयरियों और आइसक्रीम विनिर्माताओं द्वारा देश में दूध की किल्लत की जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, वे पूरी तरह खुद के लाभ से प्रेरित हैं। वे सस्ता कच्चा माल हासिल करना चाहते हैं। यह किसानों और उपभोक्ताओं के हित में नहीं है।' जीसीएमएमएफ अमूल ब्रांड के दूध और अन्य उत्पादों का उत्पादन करती है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि डेयरी कंपनियों द्वारा दिसंबर में दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने से एसएमपी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में चारा अत्यधिक महंगा हो गया है, जिसकी वजह पिछले साल महाराष्ट्र और कर्नाटक भारी बाढ़ जैसी प्रतिकूल मौसम है। इसके अलावा पिछले साल बाढ़ में लाखों पशु बह जाने से दूध की आपूर्ति प्रभावित हुई है। सतीश ने कहा, 'एसएमपी के आयात को मंजूरी देने से किसानों की आमदनी घटेगी, जिससे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी दूर हो जाएगा। यह खाद्य तेलों में भारत की गलती का दोहराव होगा।'

उन्होंने कहा कि तीन दशक पहले भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर था। आज भारत में खाद्य तेल की 65 फीसदी मांग आयात से पूरी हो रही है। इसकी वजह नीतिगत दखल ही थी। एक निजी डेयरी के अधिकारी ने कहा, 'सहकारी डेयरियां केवल किसानों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन निजी डेयरियां उपभोक्ताओं को लेकर भी फिक्रमंद हैं। इसलिए आयात से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।'

- एसएमपी के दाम एक महीने में 15 फीसदी और पिछले एक साल में 100 फीसदी बढ़े
- पिछले साल बाढ़ के बाद दूध की किल्लत पैदा होने से बढ़ीं कीमतें
- आइसक्रीम विनिर्माता चाहते हैं कि 50,000 टन एसएमपी का शुल्क मुक्त आयात हो
- इसका सहकारी डेयरियां कर रही हैं विरोध
- उन्हें डर है कि इस कदम से उन्हें और किसानों को नुकसान होगा

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 7	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,698.0	-6.6	1,974.8	4.6
Copper	5,726.0	-3.6	6,302.5	2.6
Nickel	13,010.0	-20.2	13,725.5	-20.2
Lead	1,844.0	-12.4	2,100.8	-2.6
Tin	16,575.0	-0.2	17,507.0	0.6
Zinc	2,206.0	-13.2	2,451.0	-10.8
Gold ($/ounce)	1,566.0*	6.6	1,764.4	5.5
Silver ($/ounce)	17.7*	3.6	20.1	1.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	53.9*	-14.0	54.9	-11.2
Natural Gas ($/mmBtu)	1.9*	-33.2	1.9	-33.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	195.4	6.6	290.6	-5.0
Maize	183.5*	1.4	261.8	-7.5
Sugar	423.0*	27.4	489.8	-0.4
Palm oil	690.0	11.7	1,161.6	19.5
Rubber	1,320.9*	-9.2	1,876.8	5.7
Coffee Robusta	1,271.0*	-5.8	1,806.7	-5.4
Cotton	1,490.3	5.1	1,577.7	-1.9

* As on Feb 7, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	68.3	37678
Oil and Oilseeds	259.5	72365
Spices	0.1	10
Metal(Feb 06)		
Metal- non ferrous	5636.6	42611
Metal- precious	9843.6	366
Oil and gas(Feb 06)		
Gas	2844.2	50219
Oil	20356.8	3057

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	167.0	132943
Grains	163.7	96685
Oil and Oilseeds	739.6	454830
Others	126.7	64035
Pulses	71.7	45835
Spices	51.4	21443

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Feb 25)	135.6	2.0
Silver Micro (Feb 28)	46241.0	1.1
Silver (Mar 05)	46220.0	1.1
Silver Mini (Feb 28)	46238.0	1.1
Aluminium Mini (Feb 28)	138.6	0.9
Losers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Feb 28)	748.7	-2.0
Kapas (Apr 30)	1058.5	-1.6
Crude Oil (Feb 19)	3630.0	-1.4
Cotton (Feb 28)	19150.0	-1.0
Zinc Mini (Feb 28)	172.2	-0.9
Nickel (Feb 28)	957.1	-0.8
Zinc (May 29)	175.1	-0.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Jeera Unjha (Mar 20)	13720.0	-2.1
Soyabean Indore (Feb 20)	4046.0	-1.8
Bajra (Feb 20)	1910.0	-1.6
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1793.0	-1.5
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1059.5	-1.5
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6936.0	-1.3
Guar Seed 10 (Feb 20)	3918.0	-1.3
Chana-Bikaner (Mar 20)	3874.0	-1.1
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	846.4	-1.0
Barley Jaipur (Apr 20)	1697.0	-1.0
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	3992.0	-0.9
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5904.0	-0.7
Coriander-Kota (Apr 20)	6325.0	-0.7

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1058.5	2.6
Aluminium Mum (May 29)	139.9	1.0
Copper Mum (Feb 28)	435.5	0.8
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19150.0	0.6
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46241.0	0.1
Alumini-Mumbai (Feb 28)	138.6	0.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1195.7	-9.1
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3575.0	-4.8
Lead Min Mumbai (Feb 28)	146.0	-3.4
Lead Mum (May 29)	148.1	-2.0
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	172.2	-1.8
Gold Petal-Mumbai (Feb 28)	4005.0	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1910.0	2.4
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	750.6	1.2
Moong-Merta City (Feb 20)	7682.0	0.9
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3107.0	0.2
Maize-Sangli (Feb 20)	1869.0	0.1
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	18940.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1697.0	-20.8
Jeera Unjha (Mar 20)	13720.0	-5.2
Soy Bean Indore (Feb 20)	4046.0	-3.4
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6936.0	-1.8
Coriander-Kota (Apr 20)	6325.0	-1.7

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	105......(105)
Aluminium ingots /kg	141......(141)
Brass sheet cutting /kg	325......(325)
Brass utensil scraps/kg	310......(312)
Copper heavy scrap /kg	415......(420)
Copper utensil scraps/kg	394......(394)
Copper wire bar /kg	450......(451)
Lead ingots /kg	150......(150)
Nickel Cathodes /kg	980......(980)
Tin slabs /kg	1250......(1245)
Zinc slabs /kg	175......(177)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10236......(10236)
DCH - 32 /Qtl	11332......(11332)
Jaydhar /Qtl	9758......(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11079......(11107)
Source:Cotton Association of India	
Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	843......(837)
Castor Comm /10kg	833......(827)
Ricebran oil/10kg	820......(-)
Groundnut oil /10kg	1140......(1140)
Linseed oil /10kg	900......(-)
Karanji /10kg	800......(-)
Palm oil /10kg	853......(840)
Sunflower exp ref /10kg	880......(870)
Sunflower oil exp /10kg	830......(830)
Soyabean ref / 10kg	863......(855)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3612 ......(3382-3622)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	50.74......(50.95)
Brent Crude (UK)	54.05......(54.48)
Brent Crude (WTI)	50.95......(50.95)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.85......(1.86)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	286.51 ......(287.97)
Naptha spot /Rs/MT	45170......(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150......(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950......(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40503......(40336)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40666......(40498)
Silver.999/ kg	46230......(46155)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18891.05	18931.40
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.35	138.50
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1900.00	1910.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1867.75	1865.55
Barley Jaipur (N)	1 Q	2148.75	2142.35
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3758.00	3758.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4026.20	4020.35
Castor Seed-Kadi (N)	X	3995.00	3990.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	3992.85	3968.20
Chana Delhi (N)	1 Q	4214.05	4200.00
Chana-Akola (N)	X	3925.00	3937.50
Coriander-Gondal (N)	X	6307.00	6320.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6366.65	6300.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6493.15	6435.25
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1863.60	1874.60
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1915.45	1928.70
Cotton-Kadi (N)	1 B	18958.85	18979.20
CPO-Kandla (M)	10 K	768.50	770.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	748.10	741.55
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	740.00	740.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	902.55	904.75
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1548.60	1548.85
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3455.05	3450.45
Gold Ahm (M)	10 G	40406.00	40556.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32455.00	32575.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4048.00	4063.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7038.55	7066.65
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3937.90	3950.00
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3863.00	3892.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1091.75	1093.25
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.15	103.40
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15000.00	15000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14596.30	14474.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	845.90	840.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1021.65	1023.25
Kapas-Rajkot (N)	X	1013.40	1018.50
Lead Mum (M)	1 K	153.50	151.10
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1850.00	1878.75
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2120.85	2115.90
Maize-Erode (N)	X	1806.65	1790.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2120.85	2115.90
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2025.00	2010.00
Maize-Sangli (N)	X	1864.55	1867.75
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4650.00	4631.25
Moong-Merta City (N)	1 Q	7665.00	7611.10
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4256.75	4231.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	973.10	968.80
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3176.00	3160.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	327.80	328.20
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33000.00	32855.55
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	837.50	830.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	775.00	773.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1901.65	1891.25
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5357.00	5365.65
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	830.00	829.40
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	871.50	869.20
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	868.05	864.00
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	870.00	865.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13400.00	13400.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13350.00	13375.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46143.00	46205.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4232.00	4189.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4100.00	4082.75
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4332.90	4267.25
Soy Bean-Akola (N)	X	4250.00	4200.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33700.00	33000.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	871.60	870.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31410.00	31470.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31710.00	31700.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28670.00	29020.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3265.00	3270.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3404.75	3366.80
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3288.75	3285.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3466.65	3476.20
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3283.00	3278.50
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3150.00	3150.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5900.00	5908.35
Wheat Delhi (N)	1 Q	2210.00	2210.60
Wheat Kota (N)	1 Q	2175.00	2176.65
Wheat New Indore (N)	1 Q	2155.00	2180.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2120.00	2105.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2185.00	2195.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5550.00	5575.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	175.30	175.40

* as on Feb 06, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19290, 19340, 19110, 19150	3746	569	28104
Mar 31	19530, 19610, 19390, 19420	1888	259	7423
Apr 30	19810, 19810, 19670, 19710	247	15	1254
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1818, 1843, 1784, 1793	19360	1422	34640
Mar 20	1832, 1862, 1802, 1811	54840	3834	71350
Apr 20	1864, 1885, 1828, 1839	4500	387	18810
May 20	1884, 1910, 1858, 1876	730	70	4780
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1072, 1075, 1055.5, 1058.5	248	59	888
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1072, 1074.5, 1056, 1059.5	1006	559	3363
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	1920, 1920, 1910, 1910	40	2	120
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1701, 1701, 1690, 1697	640	33	2420
May 20	1701, 1705, 1694, 1698	480	20	2130
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3964, 3970, 3914, 3918	13845	1405	26055
Mar 20	4006, 4018, 3956, 3962	25645	2693	63365
Apr 20	4050, 4052, 3996, 4000	1235	153	2595
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3880, 3892, 3862, 3874	3160	252	8475
Mar 20	3900, 3906, 3880, 3890	3695	416	21335
Apr 20	3910, 3920, 3894, 3902	730	105	5085
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	751.5, 761.1, 747, 748.7	20370	1597	44750
Mar 31	744.5, 754.8, 741, 741.9	10750	755	20880
Apr 30	747.8, 754.8, 738.8, 740	1110	94	6490
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1195.6, 1209.9, 1194.2, 1195.7	123.12	298	171.36
Mar 31	1198, 1200, 1187.3, 1188	20.88	43	70.2
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4005, 4038, 3981, 3992	8530	715	7800
Apr 20	4060, 4085, 4041, 4052	15520	1183	16970
May 20	4074, 4105, 4069, 4091	740	64	3890
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	850, 855.6, 845.2, 846.4	12055	1347	24320
Mar 20	836, 844.4, 833.2, 834.2	19640	2280	54710
Apr 20	831.8, 840.8, 830.4, 831	2035	293	5665
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4112, 4144, 4024, 4046	16855	1851	54585
Mar 20	4110, 4136, 4022, 4050	46415	5389	146850
Apr 20	4120, 4136, 4032, 4050	14750	1758	88695
May 20	4134, 4160, 4060, 4074	1765	252	16045
Jun 19	4130, 4130, 4098, 4122	80	16	285
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7040, 7040, 6928, 6936	6020	735	9150
Mar 20	7120, 7132, 7007, 7019	10770	1428	52395
Apr 20	7177, 7188, 7100, 7127	1205	111	2490
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3900, 3907, 3862, 3874	9950	767	22920
Apr 20	3906, 3906, 3867, 3876	5100	451	17120
May 20	3940, 3940, 3914, 3919	2090	182	4650
Jun 19	3971, 3981, 3970, 3972	1270	103	1090
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Mar 13	3625, 3650, 3625, 3636.7	0.3	3	5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6366, 6368, 6279, 6325	2040	188	7610
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14045, 14045, 13565, 13720	1377	410	2121
Apr 20	13780, 13780, 13520, 13630	957	293	1722
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5942, 5956, 5888, 5904	740	133	4775
Apr 20	5886, 5912, 5842, 5872	365	65	4335
May 20	5940, 5940, 5940, 5940	10	2	130

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	139, 139.2, 138, 138.1	3990	2850	5271
Mar 31	139.25, 139.3, 138.5, 138.6	86	76	438
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	433.5, 434.95, 431.1, 431.55	16597.5	5463	12585
Mar 31	436.35, 436.5, 433.05, 433.35	287.5	113	1187.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	146.15, 146.2, 144.9, 145.2	6630	4345	5836
Mar 31	146.8, 146.8, 145.7, 146	138	123	636
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	959.9, 962.2, 951.5, 952.6	11620.5	7002	3205.5
Mar 31	958.1, 960.2, 951.6, 953.7	151.5	99	244.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	172.65, 172.65, 170.45, 170.6	22993	13281	20095
Mar 31	173.45, 173.45, 171.8, 171.9	1894	1124	3470
Apr 30	173.2, 173.2, 173.2, 173.2	1	1	7
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40393, 40600, 40302, 40527	6.17	5289	17.45
Jun 05	40582, 40750, 40446, 40709	0.42	283	5.63
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32269, 32323, 32205, 32305	0	245	0.01
Mar 31	32217, 32319, 32204, 32292	0	38	0
Apr 30	32289, 32346, 32289, 32308	0	3	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40345, 40518, 40232, 40445	0.84	7222	0.84
Apr 03	40411, 40555, 40280, 40491	0.15	1323	0.32
May 05	40469, 40631, 40395, 40566	0	24	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	3996, 4020, 3996, 4016	0	909	0.01
Mar 31	4021, 4034, 4020, 4031	0	260	0
Apr 30	4020, 4040, 4020, 4039	0	6	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46200, 46375, 46033, 46236	240.15	6578	269.55
May 05	46709, 46889, 46560, 46807	6.24	194	27.42
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46250, 46385, 46061, 46263	30.27	22093	27.38
Apr 30	46610, 46899, 46583, 46771	2.37	1837	6.4
Jun 30	47080, 47303, 47080, 47236	0.01	9	0.17
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46200, 46388, 46057, 46260	83.01	13539	47.89
Apr 30	46769, 46900, 46582, 46768	2.75	512	7.4

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	134.6, 134.6, 132, 133	78175mb	34838	52326mb
Mar 26	136.6, 136.7, 134.7, 135.4	3433mb	1947	6020mb
Apr 27	140.7, 140.9, 139.2, 139.7	313mb	148	325mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3650, 3673, 3613, 3623	19541bl	111430	3519bl
Mar 19	3684, 3697, 3643, 3651	512bl	4322	385bl
Apr 20	3652, 3694, 3652, 3673	0bl	2	4bl

सायं सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19330, 19410, 19280, 19350	2338	361	28014
Mar 31	19570, 19660, 19550, 19620	1182	156	6730
Apr 30	19860, 19910, 19840, 19870	361	54	1088
May 29	19990, 19990, 19990, 19990	04	1	09
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1070, 1076.5, 1070, 1071.5	644	122	828
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1072.5, 1077.5, 1069, 1073	1189	613	3449
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	766.7, 774, 748.1, 750.9	30020	2197	43870
Mar 31	757.1, 763.3, 742.1, 744	20400	1382	20110
Apr 30	754.3, 762, 741.1, 744.3	4440	348	6270
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	861.8, 863.4, 847.6, 849	24400	2117	26735
Mar 20	847.8, 851, 832.8, 834.8	26600	2767	53065
Apr 20	841.8, 847.6, 828, 829.6	2465	334	5595

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	137.25, 138.95, 136.75, 138.6	13649	9142	4802
Mar 31	138.1, 139.4, 137.3, 139.05	450	398	426
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	435.5, 439.45, 433.4, 435.5	41440	13785	9645
Mar 31	439.6, 440.2, 434.9, 437.3	777.5	302	1162.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.5, 146.65, 144.85, 146	18489	11297	5094
Mar 31	146.5, 147.2, 145.6, 146.75	359	301	588
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	961.6, 967.4, 953.3, 957.1	24438	14528	1963.5
Mar 31	961.4, 965.8, 952.6, 956	369	168	202.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	176.1, 176.3, 173.6, 175.1	8	8	15
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	174.2, 174.6, 171, 172.2	52503	29624	15584
Mar 31	175.1, 175.25, 172.5, 173.5	2311	1598	3107
Apr 30	174.5, 174.5, 173.2, 173.75	5	5	8
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40081, 40421, 40030, 40351	11.32	9591	16.55
Jun 05	40254, 40565, 40201, 40538	0.43	338	5.37
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32134, 32250, 32100, 32227	0.01	485	0.01
Mar 31	32095, 32269, 32095, 32209	0	82	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40043, 40345, 39972, 40287	1.56	13736	0.77
Apr 03	40091, 40384, 40019, 40323	0.26	2252	0.28
May 05	40195, 40425, 40141, 40379	0.01	78	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	3991, 4010, 3984, 4005	0.01	2201	0.01
Mar 31	4005, 4022, 4003, 4020	0	450	0
Apr 30	4038, 4038, 4002, 4020	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45800, 46328, 45761, 46220	613.62	17175	242.22
May 05	46319, 46804, 46271, 46749	12.06	382	26.61
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45820, 46333, 45769, 46241	83.25	59417	23.3
Apr 30	46312, 46846, 46300, 46766	7.41	5407	6.25
Jun 30	46800, 47250, 46800, 47112	0.03	29	0.16
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45808, 46338, 45776, 46238	224.07	35753	37.78
Apr 30	46374, 46843, 46313, 46762	8.04	1466	7.11

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	133.4, 136.1, 131.1, 135.6	203858mb	91501	44159mb
Mar 26	136.3, 138.4, 133.6, 137.9	8625mb	5299	5778mb
Apr 27	140.6, 142.1, 138, 141.8	439mb	316	283mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3689, 3719, 3583, 3630	54248bl	312686	2686bl
Mar 19	3720, 3743, 3614, 3658	1545bl	13010	367bl
Apr 20	3740, 3754, 3658, 3685	3bl	15	4bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

`बम-बंदूक का छोड़ें रास्ता'

फोटोः पीटीआई

बोडो उग्रवादियों के साथ शांति समझौते को मोदी ने असम में नई सुबह की शुरुआत बताया

बोडोलैंड के लिए सशस्त्र आंदोलनों का दंश झेल चुके असम में शांति की नई पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी उग्रवादियों, पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित संगठनों और नक्सलियों से हथियार छोड़ने और राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने एवं जीवन का जश्न मनाने की अपील की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बोडो शांति समझौते पर गत 27 जनवरी को हुए समझौते का जश्न मनाने के लिए असम के कोकराझार में शुक्रवार को आयोजित विशाल जनसभा में कहा कि यह समझौता असम में शांति की नई सुबह लेकर आया है। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के चलते दो बार असम दौरा टलने के बाद प्रधानमंत्री की इस यात्रा का कार्यक्रम बन पाया है। मोदी ने कहा कि पहले किसी ने पूर्वोत्तर के लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया और अशांति बने रहने दी। उन्होंने कहा, 'इस रुख ने पूर्वोत्तर के लोगों को केंद्र से अलग-थलग रखा और भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान में उनका विश्वास खत्म हो गया। बोडो समझौते से नई उम्मीदों, नए सपनों और नए हौसले का संचार हुआ है।''

मोदी की अपील

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय समूहों से भी शांति की राह पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा, 'कश्मीर, पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों और नक्सली इलाकों में जो लोग अब भी बम, बंदूक और बुलेट थामे हुए हैं... वापस आइए और मुख्यधारा का हिस्सा बनिए। लौटें और जीवन का जश्न मनाइए।'

उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) लागू होने पर असम के लोगों में व्याप्त चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि सीएए लागू होने के बाद बाहर के लाखों लोग यहां आ जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा।'

दरअसल सीएए को संसद में पारित करने के बाद से ही असम में इस कानून के विरोध में तीखे प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इन विरोध प्रदर्शनों की ही वजह से पिछले दो महीनों में दो बार प्रधानमंत्री की असम यात्रा रद्द कर दी गई थी।

पिछले 27 जनवरी को सरकार ने असम के खतरनाक उग्रवादी समूह नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के सभी गुटों, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) और यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (यूबीपीओ) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ देने की बात कही गई है लेकिन राज्य या केंद्र-शासित प्रदेश बनाने का उल्लेख नहीं है।

तेजी से होगा काम

प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चाधिकार-प्राप्त समिति के रिपोर्ट सौंपने के बाद असम समझौते की उपधारा छह को लागू करने के लिए केंद्र तेजी से काम करेगा। इसमें असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान एवं संपदा के संरक्षण-प्रोत्साहन के लिए संवैधानिक, विधायी एवं प्रशासनिक संरक्षण देने का प्रावधान है।

इस बीच बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के प्रमुख हेगराम मोहिलारी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनसे अपील की कि एनडीएफबी के नेताओं एवं कैडर पर से जघन्य मामले भी वापस लेने की मांग की है। जहां तक गैर-जघन्य अपराधों का सवाल है तो शांति समझौते में उन्हें राज्य सरकार द्वारा हटा लेने की बात कही गई है। *एजेंसियां*

चुनाव नतीजा: बाजार का रुख सामान्य!

पुनीत वाधवा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। ऐसे में बाजार की तात्कालिक और सामान्य प्रतिक्रिया दिखना लाजिमी है। विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रतिक्रिया का इस्तेमाल दीर्घावधि की खरीदारी के लिए किया जा सकता है। हालांकि उनका कहना है कि नतीजे वाले दिन बेंचमार्क सूचकांक अस्थिर रह सकता है लेकिन बाजार फिलहाल भाजपा के खराब प्रदर्शन की आशंका नहीं जता रहा है।

बाजार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था में वृद्धि, कॉरपोरेट कमाई में वृद्धि और वैश्विक धारणा है। इक्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जी चोक्कालिंगम कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि भाजपा या राजग की जीत-हार से बाजार पर कोई असर होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनावों नतीजे की मामूली प्रतिक्रिया जरू जा सकती है। दिल्ली की ल काफी कम सीटें हैं। ऐसे

पर दिल्ली की व पर कोई खतरा बाजार का पर नहीं

बंदरगाहों पर जांच का इंतजाम

कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार ने देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को संक्रमण की तत्काल जांच, पहचान और संक्रमित लोगों को अलग करने के लिए विशेष प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। एहतियाती उपायों के तहत समुद्री नाविकों और क्रूज यात्रियों को निकालने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने यह प्रणाली लगाने का निर्देश दिया है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा कि सभी प्रमुख बंदरगाहों को एन-95 मास्क खरीदने और थर्मल स्कैनर लगाने को कहा गया है। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि चीन में कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित वुहान क्षेत्र में अभी तक 80 भारतीय छात्र मौजूद हैं जबकि देश में अब तक तीन मरीजों में कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। डॉ हर्षवर्द्धन ने बताया कि इस मामले के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह बनाया गया है।

चीन में कोरोनावायरस से फैली महामारी की वजह से माल ढुलाई की दरें कम होने की वजह से मार्च तिमाही में देश की जहाजरानी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ने की संभावना है। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) की अध्यक्ष हरजीत जोशी कहती हैं, 'माल ढुलाई की दरों में बड़ी गिरावट हुई है और इससे एससीआई पर असर पड़ रहा है। हमने जनवरी में भी नुकसान की स्थिति देखी है और इससे चौथी तिमाही की कमाई पर भी असर पड़ने की संभावना है।'

डॉक्टर की मौत

चीन में संक्रमण के बारे में सबसे पहले चेतावनी देने वाले एक चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग की मौत गुरुवार को हो गई जिससे बाद चीन में शोक का माहौल है

दक्षिण कोरिया में मास्क पहन कर शादी करते युगल

और लोगों ने सरकार के खिलाफ ऑनलाइन मंचों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। 34 वर्षीय इस डॉक्टर की मौत के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को यह आश्वासन दिया कि वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए गए हैं जिससे लगभग 640 लोगों की मौत हो गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि गुरुवार को 73 लोगों की मौत हो गई जबकि 3,143 लोगों के संक्रमण की चपेट में आने के नए मामले दर्ज किए गए। कोरोनावायरस की चपेट में आए मामलों की कुल संख्या 31,161 पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से फोन पर बात करने के बाद कहा कि चीन ने इस महामारी से लड़ने की हरसंभव कोशिश की है। ट्रंप ने ट्वीट किया, 'हम चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।'वहीं जापान ने अपने एक क्रूज जहाज पर कोरोनावायरस के कुल 61 मामले दर्ज किए। इस वायरस से चीन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है और सभी उद्योगों पर इसका असर दिख रहा है।

एजेंसियां

कंपनियां बरत रही हैं एहतियात

पृष्ठ 1 का शेष

कर्मचारियों से कहा गया है कि अगर उन्हें कोरोनावायरस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत करीब के स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।' कंपनी के मुताबिक उसकी चीन इकाई में 2,000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनमें से 98 से अधिक स्थानीय हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजिज के भी चीन में कर्मचारी हैं। उसका कहना है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और चीन सरकार के परामर्शों पर नजर बनाए हुए है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक विशेष वैश्विक कार्यबल का गठन किया है और हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सुझाव पर जरूरी कदम उठा रहे हैं। 5हमने सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के सुझावों के मुताबिक जरूरी एहतियाती कदम उठाने को कहा है। कर्मचारियों को सभी तरह के एहतियाती उपायों की जानकारी दी गई है और कर्मचारियों की सुविधा के इसे लिए कार्यालय परिसरों में डिस्प्ले बोर्ड पर लगा रखा है। प्रभावित देशों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है।' टीसीएस और इन्फोसिस भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। टीसीएस के प्रवक्ता ने कहा, 'एहतियाती उपाय के तौर पर टीसीएस ने चीन में कर्मचारियों को घर से काम करने और बेवजह घर ने नहीं निकलने को कहा है। इस तरह हम अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवा दे रहे हैं।' आईटी सेवा फर्म कैपजेमनाई के सूत्रों ने भी कहा कि कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के चीन और आसपास के देशों में आने-जाने पर पाबंदी लगाई गई है।

भारत सरकार ने 2 फरवरी को चीनी यात्रियों और चीन में रह रहे विदेशियों के लिए ई-वीजा सुविधा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी। आईटी उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि इससे दीर्घावधि में लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। सबरवाल ने कहा कि चीन के वुहान में कुछ ही आईटी पेशेवर थे और वे भी वहां आवाजाही बंद होने से पहले निकल गए थे। हुबेई प्रांत के वुहान से ही इस संक्रमण की शुरुआत हुई थी जिससे दुनियाभर में 31,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। इसके कारण चीन में 636 और चीन से बाहर दो लोगों की मौत हो चुकी है।